



जयपुर

बुधवार

17 जुलाई, 2024

वर्ष: 10 अंक: 93

राजस्थान का सर्वाधिक ई-पेपर दैनिक

अंदोलन नहीं अखबार

द पुलिस पोस्ट

जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा से प्रसारित

दूरभाष: 01482-45584 पृष्ठ: 08 मूल्य: 1.30 रुपये

न्यूज़ इनबॉक्स

अंबानी की शादी में बम की धमकी दी, शख्स गिरफ्तार



नई दिल्ली।

मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में बम होने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने शादी में बम होने की धमकी वाला पोस्ट किया था। आरोपी की पहचान 32 साल के इजीनियर विरल शाह के रूप में हुई है। इस शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया था। उसने अपने पोस्ट में लिखा था- मेरे दिमाग में यह बात आ रही है कि अगर अंबानी की शादी में बम फटा तो आधी दुनिया उलट जाएगी। इसके बाद मुंबई में समारोह स्थल जियो सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

नवदीप जलवेड़ा को जमानत, किसान बोले-रिहाई के लिए प्रदर्शन करेंगे



चंडीगढ़।

हरियाणा-पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में मोटियों के बाद किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ सामान इकट्ठा करने में समय लगेगा, उसके बाद हम दिल्ली की तरफ खाना हो जाएंगे। किसानों ने किसान शुभकरण के मौत मामले में गिरफ्तार किसान टास्क फोर्स को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के अधिकारी को जांच देने से इंसाफ की उम्मीद नहीं बचती।

गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत



अहमदाबाद।

गुजरात में चांदीपुरा वायरस से चलते 5 दिन में 6 बच्चों की मौत हो गई है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि अभी तक राज्य में 12 बच्चों इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। इस वायरस का इन्फेक्शन 9 साल से 14 साल के बच्चों को ही होता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टरों ने बताया कि चांदीपुरा वायरस से बच्चों में फीवर और पल्ट जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके बाद इन्फेक्टाइटीस यानी दिमाग में सूजन तक हो सकती है, जो बच्चों की मौत का कारण बन सकती है। यह वायरस मच्छर और मक्खियों से इंसानों में फैलता है। ऋषिकेश ने बताया कि फिलहाल राज्य में 12 बच्चों में से 4 साबरकाण्ड, 3 अरावली, 1 महीसागर, 1 खेड़ा और 2 राजस्थान, 1 मध्य प्रदेश से हैं।

शून्यकाल के दौरान विधायक के तंज पर जोरदार बवाल: महंगी और अवैध बजरी का उठा मामला

बजट चर्चा के आखिरी दिन भी हंगामा..

सदन में गूंगा 'भाया रे भाया, खूब खाया'!

जयपुर।

विधानसभा में मंगलवार को शून्यकाल में अंता विधायक कंवरलाल ने पचीं के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र में महंगी और अवैध बजरी का मामला उठाया। इस दौरान पूर्व खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया का नाम लेने पर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। विधायक ने भाया को भ्रष्टाचार बताया और सरकार से सजा दिलाने की भी मांग रखी। इस दौरान विपक्ष के नेता टीकाराम जूल और विधायक गोविंद सिंह डोटसरा ने टोकटाकी भी की।

कंवरलाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जब से भाया को मंत्री बनाया, उसी दिन से अवैध खनन का बोलबाला शुरू हो गया। वे भ्रष्टाचार के ब्रांड एंबेसडर हो गए। भाया का नाम लेते ही सदन में हंगामा होने लगा। इस पर कंवरलाल ने कहा कि बार-बार राहुल गांधी की तरह मुंह खोल कर खड़े हो जाते हैं। कंवरलाल यहीं रुके, उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्ष के लोगों से आप बार-बार तरह खड़े हो जाते हैं। विधायक ने कहा कि बीसलपुर बांध में बजरी का ठेका जिसे दिया है, यह एनजी गडियाल कौन हैं, जिसे 28,000 करोड़ का ठेका दिया है, यह भाया का पार्टनर है।

विधायक ने कहा कि आपकी पार्टी से सांगोद से जो विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या-क्या नहीं किया। अंत में यह भी कहा, 'भाया रे भाया, खूब खाया', एक तो पूरा गांव ही खाया। विधायक ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में दो नदियां बहती हैं, लेकिन फिर भी बजरी महंगी है। सरकार को चाहिए कि गरीबों को घर बनाने के लिए बजरी सस्ती उपलब्ध करवाए। अंता विधायक ने यह भी कहा कि ऐसे 'सदार' रहे कैबिनेट मंत्री को सजा दिलाई जाए।

एनजी गडियाल को 28,000 करोड़ का ठेका देने की भी गूज

- वित्त मंत्री दीपा कुमारी ने बजट पर बहस का जवाब भी दिया
- पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को जगकर कोसा



कांग्रेस ने कर्ज लेकर घी पीया- बहस के जवाब में बोली दीपा

उपमुख्यमंत्री दीपा कुमारी ने बजट बहस पर जवाब देते हुए कांग्रेस सरकार में वित्तीय व्यवस्था पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज लेकर घी पीया। 2017-18 में बीजेपी सरकार 3.04 प्रतिशत राजकोषीय घाटा छोड़कर गई थी, लेकिन पिछली सरकार अनियंत्रित तरीके से घाटा 4.26 प्रतिशत तक ले गई। इसे कम करके हम इस वित्तीय वर्ष में 3.93 प्रतिशत

तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। दीपा कुमारी ने राजस्थान के घाटे की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस ने कर्ज लेकर घी पीया और इसी सोच के साथ पांच सितारा होटल के बंद कमरों में अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार का कर्ज बढ़ गया।

इस बार किसानों के लिए 7 हजार करोड़ ज्यादा दिए

दीपा कुमारी के भाषण के दौरान कई बार विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। स्पीकर वासुदेव देवनाबी ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा। इस दौरान दीपा कुमारी ने भी विपक्षी सदस्यों पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पिछली सरकार की तरह किसानों के लिए तथ्यहीन, शोथी घोषणाओं की बजाय किसानों को संबल देने का काम करेगी। हमारी सरकार ने गहलोट सरकार के 2023-24 के बजट के मुकाबले इस बार 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है। हमने किसानों के लिए 96 हजार 787 करोड़ 27 लाख का प्रावधान किया है।

पेयजल के लिए पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, बस बैठे-बैठे बनाते रहे करिश्तियां

वि त्त मंत्री दीपा कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार ने राजस्थान में पानी के लिए कोई काम नहीं किया, बस बैठे-बैठे करिश्तियां बनाते रहे। राजस्थान में जलजीवन मिशन को लागू नहीं करा सके। हमें कहते हैं कि पानी की व्यवस्था करो। हमने तो कुछ समय में ही इसे लेकर बड़े काम किए हैं। दीपा कुमारी ने विपक्षी सदस्यों द्वारा बजट पर सवाल उठाने को लेकर कहा कि जब आपकी सरकार थी, तब यह सुझाव दे देते तो राजस्थान का नुकसान नहीं होता।

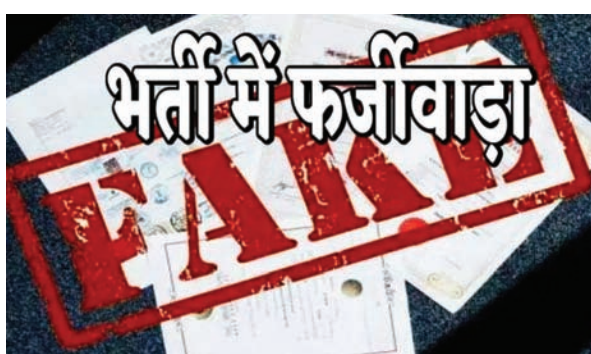
जिला परिषद की जिला स्थापना समिति की बैठक

भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोपी ग्राम सेवक व 7 शिक्षक राजकीय सेवा से बर्खास्त

बांसवाड़ा।

ग्राम सेवक व 7 थर्ड ग्रेड शिक्षकों को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह निर्णय जिला परिषद की जिला स्थापना समिति की बैठक में सोमवार शाम को किया गया। जिला प्रमुख रेशम मालवीया की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी मावजू खोटा, कलक्टर प्रतिनिधि के रूप में जिला कोष अधिकारी, एसीओ, लीगल एक्सपर्ट व अन्य अधिकारी मौजूद थे। सीईओ वीसी गर्ग ने बताया कि बैठक में ग्राम विकास अधिकारी सकन सिंह खडिया के साथ ही थर्ड ग्रेड के 7 शिक्षकों को बर्खास्त किया है। इनके खिलाफ दुराचरण की रिपोर्ट मिली है। शिक्षा विभाग की ओर से 19 शिक्षकों को सस्पेंड किया था, उनका भी अनुमोदन कर दिया गया है।

12 को जेल भेजा जा चुका, बांसवाड़ा से ही गायब हो गया छगन



इनको किया बर्खास्त

बादर गरासिया, महेश चंद्र पटेल, अनूप डोडियार, महेंद्र सिंह, गीता देवदा, खातू राम और सविता डोडियार एवं ग्राम विकास अधिकारी

सकन सिंह खडिया की सेवाएं समाप्त की गईं। शिक्षा विभाग को मिली दुराचरण रिपोर्ट में बताया गया है कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है। इन्होंने राजकीय सेवा का लाभ

उम्मी अरथियों बैठकर वर्ष 2016 में नौकरी पाने के आरोप

कुशलगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सज्जनगढ़ के राजकीय अंबेडकर छात्रावास के चार्जमन को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 12 जुलाई को कुशलगढ़ थाने में मामला दर्ज किया था। अब पुलिस इस मामले में गहनता से पूछताछ करेगी। पुलिस के अनुसार कुशलगढ़ क्षेत्र के लोहारिया बड़ा निवासी नरेंद्रसिंह अड ने वर्ष 2016 भर्ती के जरिए नौकरी हासिल की थी। इस मामले

में जांच पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी के स्थान पर किसी और ने डमी के रूप में बैठकर परीक्षा पास कराई थी। इसकी पूरी व्यवस्था सज्जनगढ़ में एकाउंटेंट के रूप में कार्यरत शंकरलाल पटेल ने की थी। डीएसपी शिवन्या सिंह ने बताया कि इस मामले में सोमवार को आरोपी नरेंद्र सिंह अड को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी।

गलत तरीके से लिया। साथ ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। कोर्ट में भी 2 बार या इससे अधिक

बार पेश किया गया है। ऐसे में कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिली है।

ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर ने पुणे कलेक्टर पर किया केस

पुणे।

पूजा ने संघ लोक सेवा आयोग को दिए हलफनामे में दावा किया है कि वह मानसिक रूप से अक्षम हैं और उन्हें देखने में भी दिक्कत होती है। पूजा ने मेडिकल टेस्ट देने से 6 बार मना किया था, जबकि यह जरूरी होता है। यूपीएससी में नियुक्ति को लेकर विवादों में गिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर ने पुणे के कलेक्टर सुहास दिवासे के खिलाफ हैरिसमेंट की शिकायत की है। पूजा के विवादों में घिरने के बाद पुणे कलेक्टर ने ही उनका

ट्रांसफर वाशिम कर दिया था। इधर, दोपहर में ही पूजा खेडकर की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई है। पूजा को 23 जुलाई तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में रिपोर्ट करने को कहा गया है। जांच पूरा होने तक वह यहीं रहेगी। महाराष्ट्र सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन जगरे ने 16 जुलाई को संबंधित आदेश जारी किया है। इससे पहले पूजा को 15 से 19 जुलाई तक अकोला में आदिवासी विकास परियोजना में प्रशिक्षु के रूप में शामिल होना था, लेकिन वाशिम जिला अधिकारी ने इस पर रोक लगा दी थी।

पति को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 6 महीने दूसरा पति जेल में रहेगा, उसके बाद महिला कैद में होगी

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को महिला और उसके दूसरे पति को 6-6 महीने जेल की सजा सुनाई है। महिला ने पहले पति से तलाक लिए बिना ही दूसरी शादी कर ली थी। पहले पति ने पत्नी, सास-ससुर और पत्नी के दूसरे पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सेशन कोर्ट से होता हुआ केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जस्टिस सीसी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि महिला और उसके दूसरे पति को एकसाथ जेल नहीं भेजा जाएगा। पहले महिला का दूसरा पति 6 महीने जेल में रहेगा। उसकी सजा पूरी होने के दो हफ्ते के भीतर महिला को पुलिस थाने में सौंप कर देना होगा।

कोर्ट के इस फैसले के पीछे का कारण कपल का 6 साल का बेटा है। बेंच ने कहा कि बच्चे की देखभाल सही से होती रहे, इसलिए अलग-अलग सजा का प्रावधान किया गया है।

सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, बेंच ने बदला एचसी का आदेश

दरअसल, याचिकाकर्ता (महिला का पहला पति) ने आरोप लगाया था कि उसका पत्नी से तलाक का मामला चल रहा था। पत्नी ने तलाक होने के पहले ही दूसरी शादी कर ली। याचिकाकर्ता ने पत्नी, पत्नी के दूसरे पति और पत्नी के माता-पिता के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

सुंझुनू के दो जवान शहीद

डोडा में आतकियों से लोहा लेते हुए शेखावाटी के जांबाजों ने दी सबसे बड़ी कुर्बानी

सिंधाना (सुंझुनू)।

शेखावाटी में देश प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। सेना में अग्रिम मोर्चा की बात की जाए तो सुंझुनू के वीर हमेशा आगे नजर आते हैं और देश के लिए एहादत देने में कभी पीछे नहीं हटते। इसी परंपरा को निभाते हुए सिंधाना क्षेत्र के दो जवानों ने देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। भैसावता कलां के 10 आरआर के जवान अजय सिंह नरुका ने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। जम्मू के डोडा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपनी शहादत दी।



हैं। चाचा कायम सिंह भी भारतीय सेना की 23 राजपूत रेजिमेंट में सिक्किम में तैनात हैं। उन्हें 2022 में सेना मेडल से नवाजा गया था।

डुमोली कलां का जवान बिजेन्द्र सिंह शहीद

सुंझुनू के सिंधाना क्षेत्र में डुमोली कलां के बिजेन्द्र सिंह दौराता भी डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। शहीद होने की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर है। शहीद के पिता रामजीलाल किसान हैं, वहीं भाई दशरथ सिंह भी सेना में लखनऊ में तैनात हैं। बिजेन्द्र सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। उनकी शादी 2019 में हुई थी। उनके दो बच्चे हैं। 4 साल के विहान व एक साल का किहान हैं। सुंझुनू के सिंधाना क्षेत्र में दो जवानों के एक साथ शहीद होने से क्षेत्र में शोक की लहर छाई हुई है।

नीट पेपर लीक केस

सीबीआई का बड़ा ऐवशन, एक और मास्टरमाइंड गिरफ्तार

नई दिल्ली।

नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मंगलवार को एक सिविल इंजीनियर समेत दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पंकज कुमार सिंह उर्फ आदित्य और राजू सिंह हैं। इस मामले में 11 जुलाई को पटना के पास से पकड़े गए आरोपी राकेश रंजन उर्फ रॉकी की तरह सीबीआई ने इनमें से एक पंकज सिंह को भी किंगपिन बताया है। मामले में अभी सीबीआई की तरफ से यह साफ नहीं किया जा रहा है कि आखिर पेपर लीक करने का असल मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में बोकारो के रहने वाले पंकज कुमार सिंह ने 2017 में एनआईटी जमशेदपुर से सिविल इंजीनियरिंग की है। आरोप है कि इसी ने हजारीबाग से



अपने साथी राजू सिंह के साथ एनटीए के पेपर लाने वाले ट्रक से पेपर चुराए थे। इसके बाद फिर पेपर लीक किए गए। राजू झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। इस मामले में मसला कई मामलों में उलझता जा रहा है। सीबीआई के सूत्रों ने सबसे पहले नीट-यूजी पेपर लीक के मास्टरमाइंड के तौर पर हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान-उल-हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम की तरफ इशारा किया था। इनमें से प्रिंसिपल के उपर ही बैंक से नीट पेपरों को सेंटर तक लाने की जिम्मेदारी थी।

बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 16 जुलाई को बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जाए, जिसमें सभी 25 हजार नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अनुवायि वाली बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने निर्देश दिया कि सभी याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर अपने काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। ऐसा ना करने पर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

बेंच का निर्देश- सभी याचिकाकर्ता 2 हफ्ते में अपने काउंटर एफिडेविट दाखिल करें



फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी सीबीआई जांच पर रोक

इससे पहले 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने पूछा था कि क्या 25 हजार नियुक्तियों में से सही तरीके से किए गए टीचर्स के अपॉइंटमेंट को अलग किया जा सकता है? चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था,

देखिए इसे किस तरह से किया गया। ओएमआर शीट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जो लोग पैन्ल में नहीं थे, उन्हें रिक्लूट किया गया। यह फॉड है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को 2016 में की गई 25 हजार 753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी 12% इंटरस्ट के साथ लौटाने के निर्देश भी दिए। इसके लिए कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है।

जयपुर की तर्ज पर अब भीलवाड़ा शहर में भी अभय कमाण्ड सेन्टर से 112 वाहनों के कैमरों की लाइव मोनिटरिंग शुरू की गई

द पुलिस पोस्ट

आज दिनांक 16-07-2024 को सभी वाहनों का निरीक्षण जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा श्री राजन दुष्यंत आईपीएस के निदेशन में गठित कमेटी प्रभारी श्रीमति अदिति चौधरी आर.पी.एस. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान निस्तारण दल भीलवाड़ा सदस्य एम.टी.ओ. रिजर्व पुलिस लाईन भीलवाड़ा व सेवा प्रदाता कम्पनी से प्रतिनिधि राजेन्द्र सिंह द्वारा FRV 112 वाहन का रिजर्व पुलिस लाईन में भौतिक निरीक्षण किया गया। वाहन FRV 112 में



उपलब्ध कराया बैट्री को हमेशा चार्ज रखने हेतु निर्देशित कर वाहन चालकों व जाता को वाहन में उपलब्ध आधुनिक उपकरणों एमडीटी/कैमरा/एनवीआर/जीपीएस/एलईडी/बैट्री को चैक किया गया 112 वाहन पर लगे चारों कैमरों का लाइव टेलीकास्ट अभय कमाण्ड सेन्टर पर शुरू कराया गया। FRV 112 वाहन में लगे पुलिस जासा को उनके निर्धारित पोइन्ट पर उपस्थित रहने व अभय कमाण्ड सेन्टर से प्राप्त सुचना पर अविलम्ब 02 मिनट के भीतर रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया। वाहन में लगे कैमरों के माध्यम से संवेदशील स्थान पर सतत निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया। रात्रि में जिस बैस पोइन्ट पर रहे वहां अपने बीकन लाईट को आवश्यक रूप से चालू रखे जिससे आने जाने वाले आमजन को वाहन पर आसानी से दिखाई पड़े हेतु पाबंद किया गया। वाहन चालकों को वाहन पर लगे कैमरा व वायरलेस सेट को 24 घंटे चालू रखने हेतु निर्देशित किया ताकि अभय कमाण्ड सेन्टर से सतत निगरानी रखी जा सके। वाहन में



हेलमेट व अन्य आपातकालीन उपकरणों से लैस किया गया है, उक्त वाहन अभय कमाण्ड सेन्टर में स्थित ईआरएसएस डायल 112 से जुड़े हुए है और इनकी वास्तविक लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। आपातकालीन स्थिति में नजदीकी पुलिस मोबाईल युनिट(FRV) 112 को भेजकर त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 01-अपने फोन से 112 डायल करें। 02-पैनिक कॉल को सक्रिय करने के लिये अपने स्मार्ट फोन पर पावर बटन को तीन बार जल्दी-जल्दी से दबायें। 03-फीचर फोन के मामले में पैनिक कॉल सक्रिय करने के लिये 5 या 9 कुंजी को दोर तक दबायें। 04-राज्य एफ एर वेबसाईट पर लॉगइन करें और अपना एसओएस अनुरोध दर्ज करें। 05-राज्य एफ उ को एसओएस अलर्ट

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत मंगलवार को जिला परिषद के सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर, हुरड़ा प्रधान कृष्ण सिंह, मांडल प्रधान शंकर कुमावत, सहाड़ा प्रधान मांगी बाई भील तथा करेड़ा प्रधान राजेंद्र सरगरा ने माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जलन कर प्रशिक्षण का शुभारम्भ किया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के डीपीएम सारंगराज दाधीच एवं डी.सी देवेन्द्र पालीवाल ने जिला परिषद



के भारत निर्माण सेवा केंद्र में ई-फाइल सिस्टम एवं ई-गवर्नेंस की महत्वाता के बारे में प्रशिक्षण दिया। मास्टर ट्रेनर के रूप में मांडल विकास अधिकारी धनपत सिंह एवं डीओआईटी कमलेश ने प्रशिक्षण दिया। अंत में प्रशिक्षण प्रभारी हिमांशु मंडिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

विश्व कौशल दिवस के उपलक्ष्य में रूडसेट संस्थान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा, विश्व कौशल दिवस के उपलक्ष्य में रूडसेट संस्थान, सुवाणा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक रवि टेलर ने बताया कि 15 जुलाई को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने विश्व कौशल दिवस को मनाने की घोषणा की। जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में कौशल के प्रति अधिक जागरूक करना है, जिससे युवा अधिक से अधिक सफल उद्यमी बन कर देश की अर्थव्यवस्था को अधिक

उंचाईयों पर ले जा सके एवं देश के विकास में अपना अहम योगदान दे सकें। इस अवसर पर संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना रोजगार कर रहे धर्मेश शाह, रोहित जाट, लाडू सिंह, सोनिया पारीक, माया वैष्णव, रेखा भाम्बी, नारायण सुथार को संस्थान की तरफ से स्मृती चिह्न देकर सम्मानित किया। इन सभी सफल उद्यमियों ने अपनी सफलता की कहानी सभी को बताई जिससे सभी छात्र, छात्राओं को एक सफल उद्यमी कैसे बने तथा व्यवसाय में सफलता कैसे प्राप्त करे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। संस्थान के दिनेश तोमर ने कार्यक्रम का संचालन किया। संस्थान के निदेशक ने आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया कि जुलाई माह में मोबाइल रिपेरिंग का प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थान में शुरू हो रहा है। जिसमें जिले के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक, युवती जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए आवेदन संस्थान में आकर या संस्थान की वेबसाईट पर कर सकते हैं।

27 जुलाई को हरिद्वार में आयोजित तथाकथित अध्यक्ष द्वारा मीटिंग पर रोक

द पुलिस पोस्ट

साण्डेराव अखिल भारतीय रांकावत ब्राह्मण सभा, दिल्ली के अध्यक्ष पद के चुनाव 21 जून 2023 को विधिवत संवैधानिक रूप से लोक तांत्रिक पद्धति से सादड़ी में आयोजित हुआ था जिसमें बाबू लाल नानेचा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हे। और उन्होंने अध्यक्ष पद का चार्ज 26 जून को एज्यूम कर लिया हे। महासभा के संयोजक महावीर प्रसाद स्वामी ने बताया की उक्त चुनाव को रोकवाने के लिए श्री मुकेश के व्यास पूर्व अध्यक्ष सभा ने सिविल कोर्ट सादड़ी, देसूरी में वाद दायर किया, यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रीट याचिका याचिका पेश की तथा रजिस्ट्रार सोसायटी महोदय को भी चुनाव रोकने हेतु पत्र लिखा किंतु उक्त चुनाव को किसी भी स्तर पर न तो अवेध घोषित किया गया, ना ही चुनाव रोकने के आदेश दिए गए। इस प्रकार माननीय न्यायालय के सानिध्य में विधिसम्मत चुनाव संपन्न किए गए तथा सभा के बाबूलाल नानेचा ही एक मात्र अध्यक्ष हे। और श्री मुकेश के व्यास ने अपनी रीट याचिका उच्च न्यायालय से वापस भी ले ली है। इस प्रकार बाबूलाल नानेचा के अलावा अखिल भारतीय रांकावत ब्राह्मण सभा दिल्ली के नाम से कोई व्यक्ति अपने आप को सभा का अध्यक्ष बताकर धमित करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही, मीटिंग, सभा, गैर कानूनन रूप से करता है अथवा उक्त कार्यवाही में कोई सहयोग भागीदार बनता है तो उनके विरुद्ध अपराधिक कृत्य अंतर्गत कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित पक्षकारों की रहेगी सूचित रहे तथा समस्त संस्थाओं के सभी सदस्य से निवेदन है की इस प्रकार की अ सामाजिक तत्वों से सचेत रहे तथा 27 जुलाई को हरिद्वार स्थित समाज भवन में किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं रखी गई है अतः नहीं पधारे।

आई एफ डबल्यू जे ब्लाक शिवगंज कार्यकारणी की घोषणा की

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज आई एफ डबल्यू जे संगठन उपखंड ब्लॉक की कार्यकारणी का गठन किया गया आई एफ डबल्यू जे संगठन सिरौही के जिला अध्यक्ष श्रीमान अशोक कुमावत के निदेशक अनुसार ब्लॉक प्रभारी श्रीमान रमेश टेलर की सहमति से आज दिनांक 16 जुलाई 2024 को ब्लॉक अध्यक्ष जैसाराम माली ने ब्लॉक की कार्यकारणी का गठन किया जो निम्न प्रकार है



उपाध्यक्ष चंपालाल माली महासचिव महेंद्र माली प्रवक्ता सुरेंद्र सिंहा भाटी कोषाध्यक्ष अशोक कुमार सोलंकी सदस्य प्रवीण राव जगदीश कुमार बने सिंह सहित अन्य की घोषणा की ब्लॉकअध्यक्ष जैसाराम माली बनने के बाद वह संगठन के आदेश अनुसार आज कार्यकारणी की घोषणा की प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ का वह प्रदेश कार्यकारणी सदस्य विक्रम सिंह करनोत सहित समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त किया

आवारा पशुओं की समस्या कब खत्म होगी

पालिका मे बोर्ड काग्रेस का होने से समस्या खत्म नहीं कर रहे है भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज नगर पालिका प्रशासन खाली अखबारों में वाह वाह करता है कि हमने आवारा पशुओं की धड़ पकड़ अभियान चालू किया पर एक भी गाय व नदी सहित किसी को भी अंदर नहीं डाला गया खाली जनता को गुमराह करने के लिए फोटो खिंचवाने के लिए कागजों में फॉर्मिलिटी के लिए कुछ पशुओं को इकट्ठा करके गौशाला के अंदर डालकर फोटो खिंचकर उन्हें वापस छोड़ा जा रहा है क्योंकि सरकारी धन का दुरुपयोग कैसे करना हो इनसे सिखा जाए तो इन अधिकारियों से सीखा जाता है नगर पालिका में कुछ बाबूजी वह इस अधिकारी के कहने पर ही चल रहे हैं भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ दिया इनको पता है कि भेरे कुछ दिन रहा है जितना लूटा जा सके लूट लो इसलिए लोगों को बुला बुलाकर बिल पास कर रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है गौशाला में पशुओं को डालना चारा खिलाना पानी पिलाना तो आता नहीं उनको गाय माता के नाम पर भ्रष्टाचार करना आता है क्योंकि उन्होंने



बहुत ही कर की हालत खराब कर दिया शहर की हर गली चौक बाजार सहित जहां भी देखो वहां पर आवारा पशुओं की लाइन लगी हुई नजर आती है कोन समझा इनको की इस जगह पर इतने पशु बैठे हैं यह लोग तो समझते हैं नहीं इनको कुछ ज्यादा कहते हैं तो वहां से पशुओं को थोड़ा उधर कर देते हैं अगर पालिका प्रशासन जो गाय माता जो जिसका मालिक शहर का नागरिक है उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए या बड़ी पेनल्टी लेनी चाहिए इससे यह आवारा पशु सड़कों पर नहीं छोड़ सके अगर कोई शासन उनके विरुद्ध कार्यवाही करता है तो शहर में



आवारा पशुओं को निकालने के लिए चार कर्मचारियों का लगाना पड़ता है तब जाकर वहाँ नहीं आती ऐसे ही सुमेरपुर से कच्चा रास्ता जाने वाले रास्ते पर दो दिन को शादी में अमृतलाल पुत्र कालूराम जी को एक नदी ने उठाकर नीचे पटक दिया जो उनका शरीर को चोट लगी है डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने को दी है पर अधिकारी वह कर्मचारी कब सुधरेंगे गाय माता के नाम पर भ्रष्टाचार कब बंद करेंगे गौमाता इन लोगों के साथ बड़ा हादसा करेगा तब जाकर उन्हें पता चलेगा कि हम आवारा पशुओं को सही वक्त पर गौशाला नदीशाला के अंदर पकड़ कर

जयपुर समेत 5 शहरों में घर खरीदने की तारीख बढ़ी

648 मकानों के लिए 15 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन, 12 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कीमत

द पुलिस पोस्ट

जयपुर। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 5 शहरों में लांच की आवासीय स्कीम में आवेदन की आखिरी तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। ये चौथा मौका है, जब बोर्ड के पास पर्याप्त आवेदन नहीं आए, जिसे देखते हुए आवेदन की अंतिम तारीख को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया। हाउसिंग बोर्ड की ओर से मार्च में 9 अलग-अलग शहरों में आवासीय योजना लॉन्च करके आवेदन मांगे थे, जिसमें से धौलपुर के बाड़ी में 13 आवास, जयपुर के प्रताप नगर 336, अलवर के पास भिवाड़ी में 15, अजमेर के पास किशनगढ़ में खोड़ा गणेश योजना के 104 और हनुमानगढ़ के न्यू आवासीय योजना डीटीओ में 180 आवासों के लिए आवेदनों की संख्या कम आई है। बोर्ड ने अप्रैल, मई के बाद जून में भी एक माह



की तारीख बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों का रुझान इन मकानों को लेकर कम है। इसे कारण इन योजनाओं में आवासों की संख्या जितने भी आवेदन नहीं आए। इसे देखते हुए बोर्ड प्रशासन ने एक बार फिर से इन योजनाओं में आवेदन की तारीख को 15 अगस्त तक

के लिए बढ़ा दिया है। अगस्त में निकलेगी योजनाओं की आवेदनों की लॉटरी इन मकानों के आवेदन मिलने के बाद इनकी लॉटरी अगस्त के आखिरी सप्ताह तक निकाली जा सकती है। सबसे

ज्यादा आवेदन उदयपुर की गोवर्धन विला स्कीम में आए हैं। यहां करीब 200 मकानों के लिए 23 हजार से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। इसी तरह माउंट आबू, जयपुर की वाटिका, जोधपुर की बड़ली और नागौर की योजना के आवेदनों की भी लॉटरी निकाली जाएगी। जोधपुर के बड़ली में करीब 1090 मकान तैयार करवाए जाएंगे। इनकी लॉटरी भी इसके साथ निकाली जाएगी। ऐसे में इन सभी 9 शहरों 3001 प्लॉट और मकानों की लॉटरी की तैयारी की जा रही है।

इन्कम ग्रुप के अनुसार बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड के ये प्रोजेक्ट इनकम ग्रुप के हिसाब से बनाए गए हैं। इनमें पांच कैटेगरी होती है। इडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी ए, एमआईजी बी और एचआईजी। आवेदक अपनी सालाना आय के अनुसार इनके लिए आवेदन कर सकता है। जैसे- इडब्ल्यूएस (इकोनॉमी वीकर ग्रुप) प्लॉट के लिए आय सीमा सालाना 3 लाख रुपए तक की है। इसी तरह एलआईजी (लोअर इनकम ग्रुप) में ये सीमा 3 से 6 लाख रुपए है। एमआईजी (मिडिल इनकम ग्रुप) में दो अलग-अलग आय वर्ग की दो कैटेगरी है। एमआईजी ए में 6 से 12 लाख रुपए और एमआईजी बी में 12 से 18 लाख रुपए है। इसी तरह एचआईजी (हाई इनकम ग्रुप) में 18 लाख से ज्यादा आय वर्ग के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कैसे कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया समझिए? स्कीम के तहत मकान पाने के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

आर्यावर्त कोलोनी मालिक एक राजनीतिक रसुखदार होने से गरीबों के भुखंड सीधा अमीरों को बेच रहे हैं

ई डब्ल्यू एस एल आई जी के भुखंड बेचकर अधिकारी व बाबुजी ने गरीबों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं

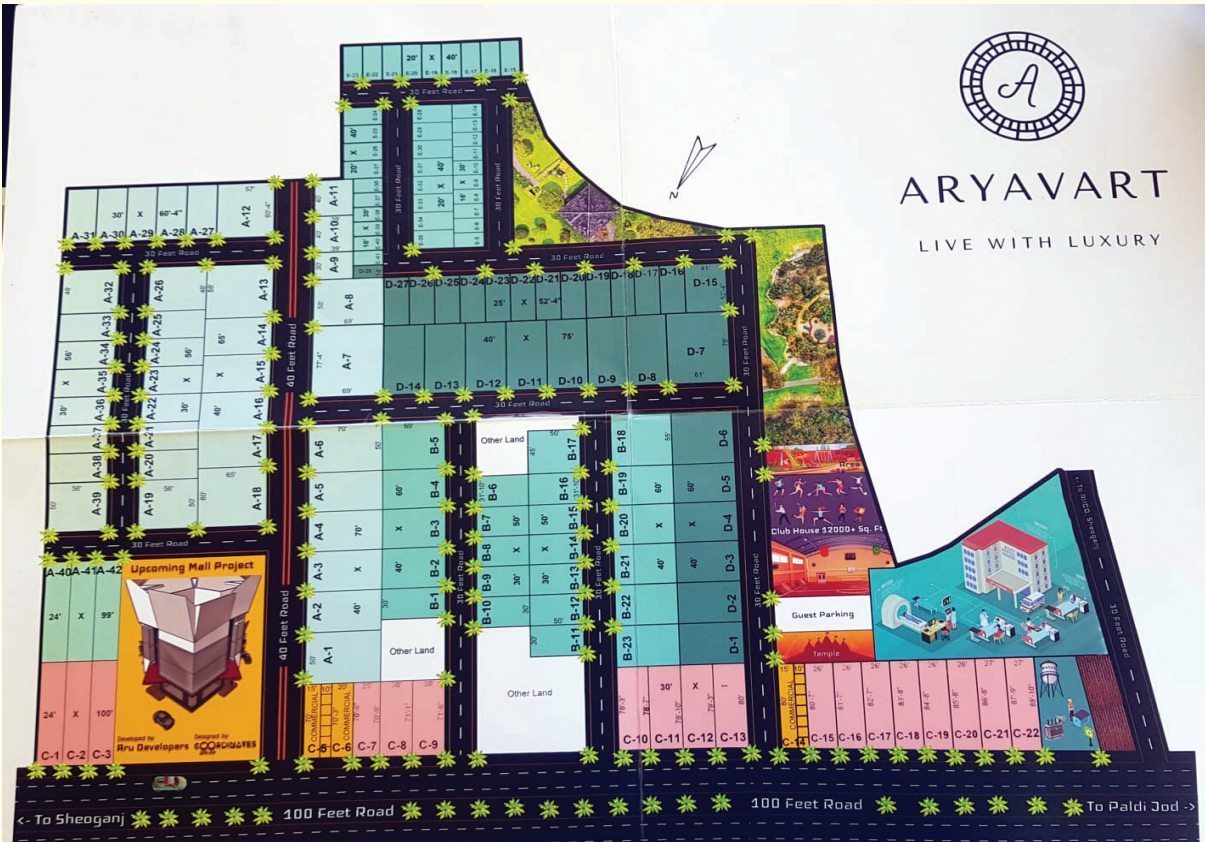
पालडी जोड रोड पर आर्यावर्त कोलोनी मालिक व पालिका प्रशासन ने मिलकर फर्जीवाडा किया है

करोड़ों कमाई के चक्कर में गरीबों के भूखंड अमीरों को बेचा गया

50 हजार का प्लॉट बेचा 6 लाख 50 हजार में सरकार व गरीबों के पेट पर लात मारी

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज नगर पालिका में गरीबों के भूखंड अमीरों को बांटे जा रहे हैं मकान शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र के अखापुरा ग्रामीण क्षेत्र में एक आर्यवर्त कॉलोनी जो की 32 बीघा से अधिक थी उसमें 9% ईडब्ल्यूएस एल आई जी के भूखंड गरीबों के लिए आरक्षित होते हैं उन भूखंडों को कॉलोनी मालिक द्वारा यहां के भूमाफियाओं के साथ मिलकर वहां पर बंगले बनाकर बेचे जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस एल आई जी के भूखंड की जगह पर कुछ दिन पहले मुहूर्त किया मुहूर्त कर वहां पर बंगले बनाने की तैयारी पूर्ण कर दी नगर पालिका द्वारा यह पट्टे लॉटरी द्वारा आवंटन होते हैं पर पालिका ने लॉटरी की कोई प्रक्रिया नहीं करके सीधे ही अमीरों को बेचने में लग गए और एक मकान की कीमत 18 लाख और 25 लाख रूपए रखी गई है क्योंकि यह पट्टा इनको फोकरट में ही मिलता है और कुछ निर्माण करके बड़ी रकम कमाने के फिराक में है क्योंकि जब यह ईडब्ल्यूएस एल आई जी के भूखंड छोड़े जाते हैं तो टाउन पॉलिसी के नियमों अनुसार नियम है यह भूकंप सभी गरीब परिवारों एससी एसटी को आवंटन किया जाए पर इन लोगों ने कोई प्रक्रिया नहीं करके सीधे ही कॉलोनी मालिक को पट्टे जारी कर दिए जो नियम विरुद्ध है यह कॉलोनी शिवगंज से पालडी जोड़ वाले रास्ते पर हैं इस कॉलोनी में और भी फर्जी वाडा खूब हुए क्योंकि फैंसिलिटी की जमीन पूरी कॉलोनी वालों के लिए आरक्षित होती है पर इस कॉलोनी मालिक ने धन देकर सिर्फ अपनी निजी अस्पताल बनाने के लिए वह पैसा कमाने के लिए एक निजी अस्पताल बनाकर लोगों से पैसा वसूल करेंगे यह जमीन तो पूरी कॉलोनी के निवास करने वाले लोगों के लिए आरक्षित थी और इसमें कुछ उल्टा सीधा कर ऊपर वालों को पैसा खिलाकर अस्पताल के लिए आरक्षित करवा दी जो नियम विरुद्ध है इस कॉलोनी का किनारा वहां पर एक बड़ा सर्किल है मास्टर प्लान के अनुसार है उस सर्किल के हिसाब से 15 मीटर उसका रेडिएशन होता है जो इसकी कुछ भाग जमीन इसमें जाती है पर पालिका कर्मचारियों अधिकारियों की साठ गांठ कर के सब उल्टा काम कर इस कॉलोनी मालिक ने पैसा फेंक कर यह सब काम करवाए जा रहे हैं इस कॉलोनी के निर्माण चालू है नहीं तो उसमें कोई साइड बैंक छोड़ा गया है और नहीं किसी प्रकार का नियम अनुसार कार्य हो रहा है आगे जो यह बंगले बना रहे हैं उसमें भी साइड बैंक नहीं छोड़ा गया है और पालिका ने इसकी स्वीकृति जारी कर दी है जो एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है या नेताओं को अधिकारियों को इसमें प्लॉट या बांगला देकर खुश किया गया है इसलिए इस कॉलोनी मालिक को फर्जी निर्माण स्वीकृति वह ईडब्ल्यूएस एल आई जी के भूखंड के पट्टे जारी कर दिए इसने आगे वाणिज्य दुकान बनाई पीछे मकान बनाएं उसमें भी साइड बैंक नहीं छोड़ा गया क्योंकि पालिका प्रशासन इस पर

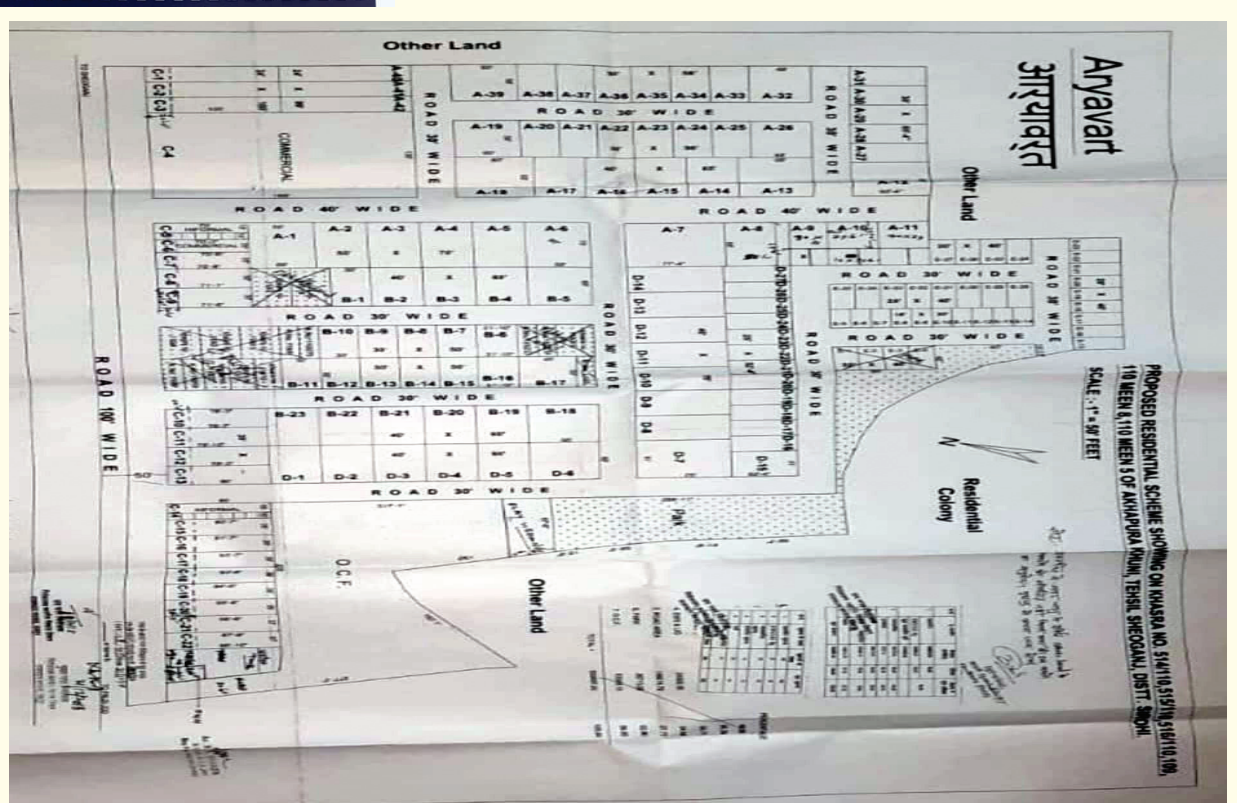


क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	प्रतिशत	योजना में कुल प्रतिशत
1.	आवासीय EWS/LIG हेतु	245970.08	90.95	50.65
2.	व्यावसायिक इन्फार्मल	28272.53	05.29	05.29
3.	पार्क	3757.41	00.70	00.70
4.	अन्य सामुदायिक सुविधा हेतु	29913.00	05.60	05.60
5.	सड़क	53349.10	10.00	10.00
	कुल क्षेत्रफल	148214.79	27.76	27.76
	कुल क्षेत्रफल	533957.00	100.00	100.00

मेहरबान है इसलिए कोई नियम पालन नहीं हो रही है और फर्जी वाडे में सभी काम चालू है इस कॉलोनी मालिक ने अभी तक सड़कें नहीं बनाई नहीं पानी के लाइन डाली है और नहीं कोई विद्युत लाइन या नाली बनाई है उसके बाद भी इसको ईडब्ल्यूएस एलआईजी के भूखंडों के पट्टे भी जारी कर दिए इनको क्या पालिका प्रशासन इतने ईमानदार है की जल्दी में इस कॉलोनी मालिक को पट्टे जारी कर दिए क्योंकि इसमें नियमों की पालना हुई नहीं है फिर यह बंगले और प्लॉट लेने वाले पैसा देकर फिर रोंपेंगे और कॉलोनी मालिक तो पैसा लेकर चले जाएंगे तुरंत इन निमाणों को रोका जाए वह पालिका प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई करावे शहर के जनप्रतिनिधि क्या कहती है शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र के अखापुरा खूनी के आर्यावर्त कॉलोनी जिसमें ई डब्ल्यू एस एल आई जी के भूखंडों की लॉटरी प्रक्रिया के अनुसार गरीबों को बांटे जाने थे पर पालिका प्रशासन ने कॉलोनी मालिक से सेंटिंग कर सीधे ही कॉलोनी मालिक को दे दिए और उसमें बंगले बनाकर बड़ी रकम कमाने के फिराक में है 50 हजार का भूखंड 6 लाख 50 हजार में बेचा

क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	प्रतिशत	योजना में कुल प्रतिशत
1.	आवासीय	245970.08	90.95	50.65
2.	व्यावसायिक	28272.53	05.29	05.29
3.	पार्क	3757.41	00.70	00.70
4.	अन्य सामुदायिक सुविधा हेतु	29913.00	05.60	05.60
5.	सड़क	53349.10	10.00	10.00
	कुल क्षेत्रफल	148214.79	27.76	27.76
	कुल क्षेत्रफल	533957.00	100.00	100.00

गया जो सरकार व गरीबों के साथ धोखाधड़ी की है जो लोगों के साथ बड़ा धोखा है जैसाराम माली पूर्व पार्श्व नगर पालिका शिवगंज शिवगंज से पालडी जोड़ सड़क पर बड़ी कॉलोनी आर्यावर्त कोलोनी में ई डब्ल्यू एस एल आई जी के भूखंड जो टाउन पॉलिसी के नियमों के तहत आवंटन नहीं किए गए यह गरीबों के हित के पट्टे थे और इसमें फैंसिलिटी की जमीन पर अस्पताल बनाकर लोगों के लूटने के प्रयास में कॉलोनी मालिक



हैं इसलिए पालिका को यह दोनों खारिज कर वापस नियम अनुसार कार्रवाई करें अन्यथा हमें न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा तब जाकर गरीब जनता के साथ न्याय होगा कमलसिंह चौहान समाजसेवी एवं गौ रक्षक शिवगंज

शिवगंज नगर पालिका में जितनी भी बड़ी जमीन पर कोलोनीया काटी है वहाँ पर दो या चार टुकड़े कर गरीबों के हित के भूखंड ई डब्ल्यू एस एल आई जी के भूखंड को सीधा बेचा जा रहा है गरीबों के साथ सब लोग व प्रशासन धोखाधड़ी

कर रहे हैं सरकारी भूखंड को छह लाख कमाई कर के व अधिकारियों को कुछ धन देकर उल्टा सीधा कार्य कर रहे हैं जो अब कब कारवाई होगी गरीबों को भूखंड मिलेंगे सीमादेवी माली पार्श्व नगर पालिका शिवगंज

समानता के बगैर लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं...



शेखर में तो हम एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य कर देंगे, परंतु हमारा सामाजिक आर्थिक ढांचा इससे नहीं बदल जाएगा, जिससे एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत को सार्थक किया जा सके। समानता का सिद्धांत सच्चे अर्थों में तभी सार्थक होगा, जब मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति की मूल्यवत्ता को साकार किया जा सके।

गांधी, लोहिया और आंबेडकर चाहते थे कि लोकतंत्र के बगैर समानता के कोई अर्थ नहीं है। तब सभी महानुभावों को यह बात समझनी चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही हमारे राष्ट्र जीवन में अच्छे परिवर्तन लाने वाली है। हमारा संविधान ही सर्वोत्तम है। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। भारत के लोकतंत्र की विश्व में प्रतिष्ठा है। संविधान के प्रति निष्ठा अधिकतम आदर्श स्थिति तक ले जाती है। किसी विषय पर केंद्रित होकर सकारात्मक चर्चा नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि कुछ राजनीतिक बिंदुओं पर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक राय न हो। राष्ट्र की अस्मिता से जुड़े मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष को राजनीति न कर राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर एक साथ होना चाहिए। गठबंधन सरकारें पहले भी रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिंहा राव की भी सरकारें गठबंधन से ही बनी थीं। इस बार भी गठबंधन सरकार है, मगर आज की स्थिति भिन्न है।

लगातार विरोध के स्थान पर शत्रु भाव बढ़ता जा रहा है। ऐसी कटुता संसदीय प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। भारत वास्तविक में संपन्न है। हमारे पास संसदीय प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। भारत वास्तविक में संपन्न है। हमारे पास संसदीय प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। भारत वास्तविक में संपन्न है। हमारे पास संसदीय प्रणाली के लिए ठीक नहीं है।

अरुण कुमार दीक्षित

भारत वास्तविक में संपन्न है। हमारे पास संसदीय प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। भारत वास्तविक में संपन्न है। हमारे पास संसदीय प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। भारत वास्तविक में संपन्न है। हमारे पास संसदीय प्रणाली के लिए ठीक नहीं है।

भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से अधिक पुरानी है। भारत में राजतंत्र और गणतंत्र शासन व्यवस्था प्राचीन है। कौटिल्य ने राज्य को अपने आप में साध्य मानते हुए समाज में सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होंने राजा के कार्य क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत बताया है। कौटिल्य ने राज्य की संपूर्ण संस्थाओं को मनुष्य के आध्यात्मिक सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण का साधन बताया है। सुझाव दिया है कि राजा को आग, बाद, महामारी, अकाल और भूकंप जैसी दैवीय विपत्तियों का निवारण करना चाहिए। राजा को चाहिए कि प्रजा के प्रति पुत्रवत् आचरण करे। राज्य में अपराधियों के लिए दंड, बाहरी शत्रुओं से रक्षा, राज्य की आंतरिक व्यवस्था एवं न्याय की रक्षा प्रमुख बताया है।

18वीं लोकसभा का गठन कुछ दिन पूर्व हुआ है। भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पिछले दिनों पूरे देश के लोगों ने संचार माध्यमों के जरिए देखी। संसद के भीतर के दृश्य काफी निराशाजनक रहे। प्रत्येक लोकसभा और राज्यसभा सदन का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित तथ्यों के अनुसार आचरण करे। उद्देशिका में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को (एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और स्वतंत्रता प्रतिष्ठा के अवरुद्ध की समता राष्ट्र की एकता और अखंडता बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं।

भारत के संविधान के अनुसार सदन के सदस्यों का आचरण होना ही मर्यादा है। बीते कुछ समय से ऐसा नहीं हो रहा है। भारी भ्रमक धनराशि खर्च कर चलने वाले लोकसभा सदन में हंगामा है। शोरा शराब की स्थिति बढ़ी है। यहां तक की शराब ग्रहण के अवसर पर विभिन्न सांसदों ने शपथ की निर्धारित शब्दावली के अतिरिक्त विशेष विचार धारा से जुड़े हुए नारे लगाए। जो संविधान समर्थ नहीं कहे जा सकते। इस पर सदन को विचार करना होगा। संसद का सदन सुचारु रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर होती है। मगर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सकारात्मक चर्चा का अभाव देखा जा रहा है। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना शुभ माना जाता है। होना यह चाहिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर राष्ट्र के लोगों को समता समृद्धि के अवरुद्ध बगैर दलीय, जातीय, पंथिक

होने को ही बड़ा अधिकार और कर्तव्य मान रहे हैं जबकि संविधान में अधिकारों के साथ कर्तव्य भी साथ-साथ अधिष्ठापित है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को राष्ट्र के प्रति निष्ठा कर्तव्य अधिकार जनता के प्रति मजबूत जवाबदेही, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिक शिक्षा, पर्यावरणीय परिस्थितिकी, नदियां, पहाड़, जंगल, पौराणिक धार्मिक पंथिक आस्थाओं एवं राजनीतिक प्रशिक्षण के उपाय पर विचार करे।

पं.जावहरलाल नेहरू संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने लोकतंत्र के सिद्धांत को महात्मा गांधी के नैतिकता के सिद्धांत के साथ मिलाकर नया रूप देने की कोशिश की। उनकी दृष्टि में लोकतंत्र अपने आप में साध्य नहीं था, बल्कि वह भारत के लाखों-करोड़ों लोगों के दुख-दर्द और गरीबी दूर करने का साधन मात्र था। (ओपी गांधी की पुस्तक राजनीति राजनीति-चिंतन की रूपरेखा पेज संख्या 344)

पं.नेहरू ने सन 1936 में लार्ड लॉथियन को लिखे गए एक पत्र में कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक लोकतंत्र को केवल इस आशा से स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि उसका परिणाम सामाजिक लोकतंत्र होगा। नेहरू ने लोकतंत्र के साथ स्वतंत्रता और समानता के अटूट संबंधों को भी स्वीकार किया है। समानता के बगैर स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। डॉ. आंबेडकर के समानता को लेकर विचार हैं कि राजनीतिक

संपादकीय

चिंता का सबब

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला निश्चित रूप से चिंता का सबब है। 40 दिन पूर्व राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले ट्रंप पर एक चुनावी सभा में जानलेवा हमले से हर कोई हलकान है। वाकई ट्रंप को जो जीवनदान मिला है वह भगवान की देन ही कही जाएगी। खुद ट्रंप ऐसा मानते हैं। दरअसल, अमेरिका में बंदूक संस्कृति की वजह से खून-खराबे का ऐसा माहौल बना है। कहते हैं कि वहां लोगों से ज्यादा बंदूकें हैं। हालांकि इस हमले को सियासी चरम से भी देखा और परखा जा रहा है। कई जानकार तो यहां तक दावा करने लगे हैं कि इस हमले के बाद ट्रंप की जीत की राह काफी आसान हो गई है। बहरहाल, ये सभी कयासबाजी मुकम्मल जांच के बाद ही साफ हो सकेंगी कि इसके पीछे किसकी साजिश है। प्रथम दृष्टया जो कुछ सार्वजनिक हुआ है उसमें हमलावर की ट्रंप के प्रति नासंदेगी की बात है। चुनाव के ठीक पहले इस तरह के हमले को लेकर कई किंतु-परंतु होते हैं। यह लगभग हर देश में होता है। अमेरिका में भी इसे लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, मगर एक बात तो हर किसी को अपने जेहन में रखनी होगी कि हिंसा और खून बहाना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए श्राप से कम नहीं। इस नाते किसी को भी इस मसले पर अपनी



त्व्रित प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। विश्व के सबसे ताकतवर मुल्क के मुखिया के पद पर रहे शास्त्र को जान से मारने की नीयत से हमला करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडन को तुरंत पूरे प्रकरण की ठोस जांच करानी चाहिए और इस बात का भरोसा विपक्षी दलों समेत देश की जनता को दिलाना चाहिए कि ऐसे कृत्य नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इस बात की भी जांच पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए कि उनकी सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के एजेंट से कहां चूक हुई। निश्चित तौर पर ट्रंप पर हमला सामान्य घटना नहीं है। इससे अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की पूरी दिशा ही बदल सकती है। ट्रंप फिलहाल बाइडन से प्रचार में बढ़त बनाए हुए हैं। बाइडन की उम्र और उप संबंधी दुश्चरियों की वजह से रिपब्लिकन पार्टी फिलवक्त कमजोर दिखती है। अगर ट्रंप पर हमले की घटना आम अमेरिकियों के दिलों-दिमाग पर गहरे तक असर डालेगी तो वहां सत्ता में बदलाव हो सकता है। देखना है, रिपब्लिकन पार्टी पूरी घटना से खुद को कैसे उबार पाती है? आने वाला वक्त वाकई दिलचस्प होने वाला है।

चिंतन-मनन

प्रयत्न में ऊब नहीं

संसार में गति के जो नियम हैं, परमात्मा में गति के ठीक उल्टे नियम काम आते हैं और यहीं बड़ी मुश्किल हो जाती है।

संसार में ऊबना बाद में आता है, प्रयत्न में ऊब नहीं आती। इसलिए संसार में लोग गति करते चले जाते हैं। पर परमात्मा में प्रयत्न में ऊब आती है और प्रयत्न पहले ही उबा देगा, तो आप रुक जाएंगे। कितने लोग हैं जो प्रभु की यात्रा शुरू भर करते हैं, पर कभी पूरी नहीं कर पाते। कितनी बार तय किया कि स्मरण कर लेंगे प्रभु का घड़ीभर! एकाध दिन, दो दिन। फिर ऊब गए। फिर छूट गया। कितने संकल्प, कितने निर्णय, धूल होकर पड़े हैं कंधों तरफ! लोग कहते हैं कि ध्यान से कुछ हो सकेगा? मैं कहता हूँ जरूर हो सकेगा। कठिनाई सिर्फ एक है, सातत्य! कितने दिन कर सकोगे? मुश्किल से कोई मिलता है, जो तीन महीने भी सतत कर पाता है। दस-पांच दिन बाद ऊब जाता है!

आश्चर्य है कि मनुष्य जिंदगी भर अखबार पढ़कर नहीं ऊबता, रेडियो सुनकर नहीं ऊबता, फिल्म देखकर नहीं ऊबता, रोज वही बातें करके नहीं ऊबता। ध्यान करके क्यों ऊब जाता है? आखिर ध्यान में ऐसी क्या कठिनाई है! कठिनाई एक ही है कि संसार की यात्रा पर प्रयत्न नहीं उठता, प्रति उठती है और परमात्मा की यात्रा पर प्रयत्न उठता है, प्रति कभी नहीं उठती। जो पा लेता है, वह फिर कभी नहीं ऊबता। बुद्ध ज्ञान के बाद चालीस साल जिंदा थे। चालीस साल किसी ने एक बार उन्हें अपने ज्ञान से ऊबते हुए नहीं देखा। कोहनूर हीरा मिल जाता चालीस साल तो ऊब जाते। संसार का राज्य मिल जाता, 23697 भूति खोकर गृह-कलह के बीज बो दिए। शक्ति के सहारे सत्ता का संचालन होता तो न रावण मारा जाता और न कौरवों को पराजय का मुंह देखा पड़ता। पिछली सदी तक भारत का शासन-सूत्र अंग्रेज संभाल रहे थे, शक्ति की उनके पास कमी नहीं थी। उनके सामने भारत छोड़ने की विवशता शक्ति की कमी से नहीं थी। ये प्रसंग प्रमाणित करते हैं कि प्रबुद्ध जनता केवल शक्ति के आधार पर शासित नहीं हो सकती।

सरकारी धन की लूट, रिश्वत और भ्रष्टाचार का साम्राज्य



सनत कुमार

आम जनता अपना वोट देकर नेता चुनती है। अपने अधिकार नेताजी को सौंप देती है। नेताजी और अधिकारी मिलकर आम जनता के विश्वास को धोखा देते हैं। फाइलों में गरीबों के नाम पर बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं। उन योजनाओं का लाभ गरीबों को आज भी नहीं मिल पा रहा है। भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली सरकार के राज में अभी भी अधिकारी और नेता मिलकर आम आदमी की जमीनों पर कब्जा करते हैं। हर काम में दलाली करते हैं। गुंडों की फौज खड़ी कर लेते हैं, इस काम में न्यायपालिका का सहारा भी नेताओं और अधिकारियों के इस गठजोड़ द्वारा लिया जा रहा है। जिसके कारण आम जनता कराह रही है। कहने को सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जनता के नौकर हैं। लेकिन अब जनता से मालिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। नेताओं के साथ मिलकर नौकरशाह आम जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लुटता आम आदमी है, उसको कानूनों के मकड़जाल में फंसा दिया जाता है। भ्रष्टाचारी

और रिश्वतखोरों के ऊपर कभी कोई कार्यवाही नहीं होती है। मध्यप्रदेश का व्यापम घोटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए नेता और अधिकारियों के गठजोड़ ने नियमों और कानून का ऐसा जाल बना दिया। जिसमें आदिवासी फंसकर फड़फड़ाते रह गए। उनकी जमीनों पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो गया। रक्षक ही अब भक्षक बन रहे हैं। न्यायपालिका द्वारा आखों में पट्टी बांधकर समर्थ लोगों को ही न्याय दिया जा रहा है। गरीब आदमी सारे जीवन अदालतों के चक्कर लगाता है। वकीलों को पैसा देता है, उसके पास जो होता है, वह भी लुट जाता है। थक-हार के घर में बैठ जाता है, यही वर्तमान का सच है। खुलेआम अवैध शराब और मादक पदार्थ बिक रहे हैं। अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। नगर पालिका, नगर निगम और अब ग्राम पंचायतों भी आम नागरिकों पर कुछ वर्षों में टैक्स और नए-नए शुल्क लगाए जा रहे हैं। सुविधा खत्म होती जा रही है। पारंप, विधायक, सांसद और मंत्री बड़े-बड़े सपने दिखाकर चले जाते हैं। सरकारी खजाने से हर विभाग को जो राशि मिलती है। नेता और अधिकारी फाइलों पर जहजिहत की योजनाओं की राशि खर्च कर आपस में बंटवारा कर लेते हैं। अनाज भी अब फर्जी तरीके से बांटा जा रहा है। सरकार कहती है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। लेकिन आधे से अधिक राशन नेताओं और सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार और मिली भगत के कारण लूट लिया जाता है। पिछले 30-40 वर्षों में नेता और अधिकारी देवताओं की तरह पूजे जा रहे हैं। विरोध करने या अधिकार मांगने पर जेल का रास्ता दिखाया जा

रहा है। हमारे नेताओं और सरकारी अधिकारियों का यह चरित्र बन गया है। शहरों में हाहाकार मचा है, पानी नहीं मिलता है। समय पर सफाई नहीं होती है। बिजली की कटौती कई बार होती है। अनाप-शनाप बिजुल भेजे जाते हैं। नेता और सरकारी अधिकारी मिलकर पहले दुग्गी बस्ती बसाते हैं। पुनर्वसन के नाम पर करोड़ों रुपए की योजना बनाते हैं। गरीबों को घर नहीं मिलते, नेताओं और अधिकारियों के दलाल उस पर कब्जा कर लेते हैं, किराए पर या बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। कई वर्षों से यह धंधा अनवरत रूप से चला आ रहा है। फर्जी वोट कार्ड, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी जमीन के पत्रों, फर्जी संस्थाएं जहां देखो, वही धपले-घोटाले खुलेआम कर रही हैं। जांच के नाम पर वर्षों तक गड़बड़ियों और घोटालों को दबाकर रखा जाता है। जब लोग भूल जाते हैं, तो जांच में जिम्मेदार व्यक्ति निर्दोष करार कर दिए जाते हैं। अभी बरसात शुरू हुई है। हर शहर नदी नालों में तब्दील हो गए हैं। थोड़ी सी बारिश में जगह-जगह पानी भर जाता है। रोड गड्ढों में बदल गई है। सूचना अधिकार कानून में अब जानकारी मिलना बंद हो गई है। संविधान में लोकतंत्र की जो परिभाषा लिखी है। वर्तमान में वह परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है। जनता का राज होगा। विधायिका और कार्यपालिका ने मिलकर मालिक को नौकर की तरह बंधक बनाकर रखा है। आम जनता से नौकरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। हर स्तर पर चौथ वसूली हो रही है। अब ऐसे संघटित गिरोह हो गए हैं, जो सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर जनता को धमकाते और डराते हैं। शासन-प्रशासन और राजनेताओं का चौथ-वसूली में संरक्षण

होता है। राजाओं के शासनकाल में राजा के सैनिक गांव-गांव में जाकर लूटमार करते थे। लगभग वही स्थिति अब बन गई है। ऐसा लगता है कि सुधार के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। न्यायपालिका भी अब शासन के अधीन होकर रह गई है। न्यायपालिका से अब न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्यायपालिका और सरकारी अधिकारियों के पक्ष में काम करते हुए नजर आ रही है। आम जनता में नाराजी और मायूसी देखने को मिल रही है। यह स्थिति धीरे-धीरे बगावत को जन्म देती है। वर्तमान शासन-प्रशासन की व्यवस्था शक्तिशाली लोगों के हाथ में केंद्रित होकर रह गई है। न्यायपालिका भी इन्हीं के प्रभाव में काम कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक बढ़हाली, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार ने आम जनता का जीना दूध कर दिया है। ऐसी स्थिति में जनता को अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सामने आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। सरकार कहती है, यदि लोगों को कष्ट होता, तो जनता सड़कर पर आती। सरकार को ऐसा लगता है, जनता के पास बहुत पैसा है। जनता पैसा खर्च कर रही है, मतलब उसके पास पैसा है। महंगाई और बेरोजगारी का कोई असर नहीं है। सरकार का मानना है, जनता को जिस दिन कष्ट होगा। वह सड़कों पर आएगी, सरकार के खिलाफ मतदान करेगी। जनता ऐसा नहीं कर रही है इसका मतलब है, सब चंगा है। चुनाव जीतना और सरकार में बने रहना ही सफलता की निशानी है। चुनाव अब जनता के वोट से नहीं प्रचलता से जीते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता की यही दुर्दशा होनी थी। जनतंत्र से एक बार फिर हम राजतंत्र की आर आगे बढ़ रहे हैं। यही वर्तमान का सच है।

केजरीवाल को जमानत के निहितार्थ



सकी है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि घोटाला हुआ ही नहीं है। हो सकता है कि यह घोटाला बहुत चतुराई के साथ किया हो, क्योंकि प्रमाण पर्याप्त नहीं हैं। केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर आम आदमी पार्टी भले ही खुशियां मना ले, लेकिन यह सत्य है कि न्यायालय ने उनके मुख्यमंत्री के अधिकार सीमित कर दिए हैं। उनको न तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अधिकार है और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

किसी भी घोटाले की जांच के लिए जांच एजेंसी कार्य करती है। लेकिन शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसी पर संदेह के बाद भी उमड़ रहे हैं। हो सकता है कि जांच एजेंसियां अपनी भूमिका को लेकर एकदम सही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी को विलेन के रूप में प्रचारित करने का अभियान सा चलता दिखाई दिया। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जांच एजेंसियों पर पहले ही सत्ता के इशारे पर कार्य करने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि जांच एजेंसियों केन्द्र सरकार के अधीन कार्य करती हैं, लेकिन जांच एजेंसियों पर यह आरोप लगाया गया है कि वे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि जांच एजेंसियों केन्द्र सरकार के अधीन कार्य करती हैं, लेकिन जांच एजेंसियों पर यह आरोप लगाया गया है कि वे गंभीर आरोप लगते रहे हैं।

केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश करने में जांच एजेंसी से अधिक भाजपा को निशाने पर लेने की राजनीति कर रही है। ऐसा नहीं है कि केवल आम आदमी पार्टी ही राजनीति कर रही है, बल्कि भाजपा भी कम नहीं है, वह भी इस मामले में बयान देने से पीछे नहीं है।

जहाँ तक भाजपा की बात है तो वह केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहले ही कह चुकी है कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। इस बात को ध्यान में रखकर यही कहा जा सकता है कि भाजपा की केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के विरोध में कार्यवाही करना चाहती है, लेकिन विपक्ष के राजनीतिक दल इसमें टांग अड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। इसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि विपक्ष के अधिकार बड़े नेता किसी न किसी आरोप में जमानत पर बाहर हैं। कई नेताओं पर गंभीर आरोप हैं और कई जेल में हैं। इसलिए विपक्ष और खास कर आम आदमी पार्टी के कदम को सरकार पर दबाव बनाने की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। हम जानते ही हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के मामले में सजायापता हैं। लेकिन इसके बाद भी वे बिहार और देश की सक्रिय राजनीति में दखल दे रहे हैं। आज हालांकि लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि सजा प्राप्त कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है।

यह है कि क्या ऐसा व्यक्ति राजनीति कर सकता है। नहीं करना चाहिए, लेकिन लालू ऐसा कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने केवल राजनीति ही नहीं की, बल्कि विपक्ष के साथ कंधे से कनधा मिलाकर खड़े दिखाई दिए। इस प्रकार की राजनीति करना किसी भी दल के लिए भी ठीक नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं माना जा सकता। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर का हो, जिसने भी किया है, उसके विरोध में कार्यवाही होना ही चाहिए। आम आदमी पार्टी भी यही कहकर दिल्ली की सत्ता पर विराजमान हुई थी। जो अब जनता के सिद्धांत से परे जाती हुई दिखाई दे रही है।

हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राजनीति प्रारम्भ करने से पूर्व अज्ञा हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उस समय कांग्रेस के केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के कारण पूरा देश उवाल में था। इसी कारण अज्ञा हजारे के आंदोलन को व्यापक रूप से सफलता मिली। इसके बाद एक ईमानदार राजनीतिक दल के रूप में आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई। बड़े बड़े वादे करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में छप्पर फाड़ समर्थन प्राप्त करके सरकार बना ली। लेकिन इसके बाद क्या हुआ। जब इनको सत्ता की चासनी चखने को मिली तो यह बौरा गए और फिर वही खेल शुरू हो गया जो चलता आया है। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार करने के जो आरोप लगे हैं, वह अभी जांच की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जांच होने के बाद यह तय हो जाएगा कि कौन कितने पानी में हैं।

दिल्ली के शराब घोटाले में जिस प्रकार से साजिश की बात कही जा रही है, उससे यह तो कहा जा सकता है कि इसमें साजिश हो सकती है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार साबित होते हैं तो यह भी एक साजिश ही मानी जाएगी, लेकिन अगर अरविन्द केजरीवाल को फंसाया गया है तो यह गंभीर साजिश ही कही जाएगी। फिलहाल इस मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब यह मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। जिसकी परतें उड़ाना बाकी हैं। अंदर क्या निकलता है, इसे देखने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।



सुरेश हिंदुस्तानी

देश को राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर चला रही राजनीति ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत देकर जांच एजेंसी पर उठे संदेह के घेरे को और बड़ा कर दिया है। अरविन्द केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश का पर्दाफाश बताया है। यहां एक सवाल यह उठ रहा है कि क्या न्याय व्यवस्था में जमानत मिलना विजय का पर्याय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसे अपना विजय और सरकारी एजेंसी की साजिश करार दे रही है। उल्लेखनीय है कि जमानत मिलने के बाद भी आरोप समाप्त नहीं हो जाता। प्रकरण चलता रहता है। अभी शराब घोटाले में न्यायालय का निर्णय नहीं आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति इसे निर्णय मानकर चल रही है। आम आदमी पार्टी का यह कदम वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने जैसा ही माना जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रारम्भ से ही यह बताने की कवायद की जा रही है कि शराब मामले में कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। उनका तर्क है कि अगर घोटाला हुआ है तो उस घोटाले की राशि भी जब्त की जानी चाहिए, जबकि प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि इससे जो राशि प्राप्त हुई उसे गोवा के चुनाव में व्यय किया गया। दोनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, यह आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन इसी मामले में आम आदमी पार्टी के अन्य नेता भी आरोपित हैं, उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल

सकी है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि घोटाला हुआ ही नहीं है। हो सकता है कि यह घोटाला बहुत चतुराई के साथ किया हो, क्योंकि प्रमाण पर्याप्त नहीं हैं। केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर आम आदमी पार्टी भले ही खुशियां मना ले, लेकिन यह सत्य है कि न्यायालय ने उनके मुख्यमंत्री के अधिकार सीमित कर दिए हैं। उनको न तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अधिकार है और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

किसी भी घोटाले की जांच के लिए जांच एजेंसी कार्य करती है। लेकिन शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसी पर संदेह के बाद भी उमड़ रहे हैं। हो सकता है कि जांच एजेंसियां अपनी भूमिका को लेकर एकदम सही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी को विलेन के रूप में प्रचारित करने का अभियान सा चलता दिखाई दिया। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जांच एजेंसियों पर पहले ही सत्ता के इशारे पर कार्य करने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि जांच एजेंसियों केन्द्र सरकार के अधीन कार्य करती हैं, लेकिन जांच एजेंसियों पर यह आरोप लगाया गया है कि वे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि जांच एजेंसियों केन्द्र सरकार के अधीन कार्य करती हैं, लेकिन जांच एजेंसियों पर यह आरोप लगाया गया है कि वे गंभीर आरोप लगते रहे हैं।

केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश करने में जांच एजेंसी से अधिक भाजपा को निशाने पर लेने की राजनीति कर रही है। ऐसा नहीं है कि केवल आम आदमी पार्टी ही राजनीति कर रही है, बल्कि भाजपा भी कम नहीं है, वह भी इस मामले में बयान देने से पीछे नहीं है।

जहाँ तक भाजपा की बात है तो वह केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहले ही कह चुकी है कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। इस बात को ध्यान में रखकर यही कहा जा सकता है कि भाजपा की केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के विरोध में कार्यवाही करना चाहती है, लेकिन विपक्ष के राजनीतिक दल इसमें टांग अड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। इसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि विपक्ष के अधिकार बड़े नेता किसी न किसी आरोप में जमानत पर बाहर हैं। कई नेताओं पर गंभीर आरोप हैं और कई जेल में हैं। इसलिए विपक्ष और खास कर आम आदमी पार्टी के कदम को सरकार पर दबाव बनाने की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। हम जानते ही हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के मामले में सजायापता हैं। लेकिन इसके बाद भी वे बिहार और देश की सक्रिय राजनीति में दखल दे रहे हैं। आज हालांकि लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि सजा प्राप्त कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है।

यह है कि क्या ऐसा व्यक्ति राजनीति कर सकता है। नहीं करना चाहिए, लेकिन लालू ऐसा कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने केवल राजनीति ही नहीं की, बल्कि विपक्ष के साथ कंधे से कनधा मिलाकर खड़े दिखाई दिए। इस प्रकार की राजनीति करना किसी भी दल के लिए भी ठीक नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं माना जा सकता। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर का हो, जिसने भी किया है, उसके विरोध में कार्यवाही होना ही चाहिए। आम आदमी पार्टी भी यही कहकर दिल्ली की सत्ता पर विराजमान हुई थी। जो अब जनता के सिद्धांत से परे जाती हुई दिखाई दे रही है।

हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राजनीति प्रारम्भ करने से पूर्व अज्ञा हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उस समय कांग्रेस के केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के कारण पूरा देश उवाल में था। इसी कारण अज्ञा हजारे के आंदोलन को व्यापक रूप से सफलता मिली। इसके बाद एक ईमानदार राजनीतिक दल के रूप में आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई। बड़े बड़े वादे करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में छप्पर फाड़ समर्थन प्राप्त करके सरकार बना ली। लेकिन इसके बाद क्या हुआ। जब इनको सत्ता की चासनी चखने को मिली तो यह बौरा गए और फिर वही खेल शुरू हो गया जो चलता आया है। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार करने के जो आरोप लगे हैं, वह अभी जांच की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जांच होने के बाद यह तय हो जाएगा कि कौन कितने पानी में हैं।

दिल्ली के शराब घोटाले में जिस प्रकार से साजिश की बात कही जा रही है, उससे यह तो कहा जा सकता है कि इसमें साजिश हो सकती है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार साबित होते हैं तो यह भी एक साजिश ही मानी जाएगी, लेकिन अगर अरविन्द केजरीवाल को फंसाया गया है तो यह गंभीर साजिश ही कही जाएगी। फिलहाल इस मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब यह मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। जिसकी परतें उड़ाना बाकी हैं। अंदर क्या निकलता है, इसे देखने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।

शिक्षा संकुल में व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ ने दिया धरना

2000 हुनरमंद व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सेवा समाप्त

द पुलिस पोस्ट

सिराही - शिक्षा संकुल जयपुर में व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण का आरोप है कि बार-बार टेंडर प्रक्रिया के कारण नौकरी से बेदखल कर दिया जाता है। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2024 को 132 स्कूलों का टेंडर समाप्त कर दिया था। हेल्थ केयर ट्रेड एवं स्टार प्रोजेक्ट के टेंडर को खत्म हुए एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। टेंडर प्रक्रिया वापस नहीं होने के कारण व्यावसायिक प्रशिक्षक विरोध कर रहे हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षकों को 10 से 15 माह तक का मानदेय भी बकाया चल रहा है। राजस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की दुर्गति हो रही है। किसी को नौकरी से निकाला गया है तो किसी किसी जिले में दस से पन्द्रह माह का तो कहीं सात माह का मानदेय बकाया चल रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षकों के परिवारों के भुखे मरने की नौबत आ गई है। राजस्थान में वर्ष 2014-15 से व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। जिसमें विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता कम्पनियों व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर ने टेंडर प्रक्रिया से राजकीय विद्यालय हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षकों को लगाया है। व्यावसायिक प्रशिक्षक कक्षा 9 वीं से 12वीं तक के हजारों विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कौशल की शिक्षा दे रहे हैं। इस केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा मिलकर व्यावसायिक शिक्षा का बजट व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय हेतु जारी किया जाता है। शिक्षा बचाओ समिति के प्रदेश संयोजक गोपाल सिंह राव के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षकों को पिछले 5 सालों से समय पर मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है। सात दस माह के बाद एक दो महिनो का मानदेय बड़े



संघर्ष के बाद मिलता है। जिसके कारण परिवार हमेशा आर्थिक संकट में रहते हैं। सिराही जिले में व्यावसायिक प्रशिक्षक

प्रदाता कंपनी इन्डियन इन्सट्यूट ऑफ रिकल डवलपमेंट गुरुग्राम कंपनी द्वारा सिराही जिले में 50 व्यावसायिक प्रशिक्षक कार्यरत है। जो कौशल विकास की शिक्षा विद्यार्थियों को दे रहे हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय की फाईल को शिक्षा विभाग द्वारा बार-बार बजट न होने के कारण पास नहीं किया जा रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षकों के कंपनी द्वारा समय पर मानदेय फाईल का भुगतान नहीं होने के कारण व्यावसायिक प्रशिक्षकों को मानदेय नहीं मिल रहा है। जिसका मुख्य कारण अयोग्य वीसी द्वारा समय पर फाईलों को जमा नहीं कराना है। साथ ही इन्डियन इन्सट्यूट ऑफ रिकल डवलपमेंट गुरुग्राम कंपनी द्वारा प्रतिमाह वेतन में से एरकट के नाम पर 601/- रुपये की कटौती की जा रही है। माह नवम्बर 2023 से आज दिन तक व्यावसायिक प्रशिक्षकों के एरकट खाते में जमा नहीं करवाये गये हैं। जिसके बारे में कंपनी के अधिकारियों व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को बार-बार मेल करके समस्या बताई जा चुकी है, परन्तु कंपनी और अधिकारियों के मिलिभगत से आज दिन तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। परेशान होकर अधिकारियों को व्यावसायिक

प्रशिक्षकों के द्वारा फोन पर और वाट्सअप पर यह समस्या बताने पर ब्लॉक कर दिया जाता है। जिससे स्थिति जस की टस नहीं हुई है। मानदेय समय पर नहीं मिलने के कारण व्यावसायिक प्रशिक्षकों को परिवार पालना भी मुश्किल हो गया है। दुकानदारों ने सात से पन्द्रह माह के राशन की बकाया राशि नहीं चुकाने के कारण उधार देना बंद कर दिया है। व्यावसायिक प्रशिक्षकों के माता पिता व बच्चों के भुख मरने की नौबत आ गई है। इनके बच्चों की स्कूल फिस बकाया होने से स्कूल जाने में भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के हजारों विद्यार्थियों को कौशल की शिक्षा देने वाले कुशल व्यावसायिक प्रशिक्षक भंयकर संकट से गुजर रहे हैं। शिक्षा बचाओ समिति राजस्थान के प्रदेश संयोजक गोपाल सिंह राव के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षक विगत पांच वर्ष से संघर्षरत है। इनकी प्रमुख मांगें शिक्षा विभाग में समायोजन, शोषणकारी प्लेसमेंट एजेंसियों से मुक्ति, रोजगार सुरक्षा, नियमित मानदेय वृद्धि, प्रसुति, मातृत्व, चिकित्सा व सभी प्रकार के अवकाश, लोकडाउन सहित सभी लम्बित बकाया मानदेय भुगतान करना है। जिसके लिये व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ राजस्थान लम्बे समय से संघर्षरत है। विरिष्ठ कर्मचारी नेता गोपाल सिंह राव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, प्रमुख शासन सचिव व शिक्षा सचिव राजस्थान सरकार से व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लम्बित मानदेय भुगतान कर इनकी न्यायोचित मांगों को मानकर राहत देने की गुहार की। इसमें दलाल कम्पनियों के द्वारा शोषण हो रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्लेसमेंट एजेंसी से नौकरी देना खत्म किया था जिसको अमलीजामा पहनाना आवश्यक है। बिचौलिया शोषण कर रहे हैं जिससे राजस्थान सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

शाहपुरा में खड़ी कार से 72 किलो मादक पदार्थ जब्त: प्लास्टिक के कट्टों में भर कर कार की बैक सीट पर रखे गए थे डोडा चूरा

द पुलिस पोस्ट

शाहपुरा-भीलवाड़ा। शाहपुरा जिला पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कांठ के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ के परिवहन और संग्रहण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत जिले भर में पुलिस द्वारा सख्ती बरती जा रही है। मंगलवार को हनुमाननगर थाना क्षेत्र के कुचल वाड़ा के पास स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक लावारिस खड़ी दिल्ली पार्सिंग कार से 72 किलो अशुद्ध डोडा चूरा पुलिस ने जब्त किया। पुलिस ने कार चालक की तलाश शुरू की, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कांठ ने बताया



कि हनुमाननगर थानाधिकारी अयूब खां को सूचना मिली थी कि हाईवे पर एक कार लावारिस खड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची और कार की तलाशी लेने पर पीछे की सीट पर प्लास्टिक के कट्टों में भरा हुआ 72 किलो

डोडा चूरा जब्त किया गया। पुलिस ने कार को जब्त कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शकरगढ़ थानाधिकारी को सौंपी गई है।

सीआईएसएफ जवान ने सुसाइड किया, छुट्टी पर घर आया था: भाई को कॉल कर पूछा था कब तक आओगे

द पुलिस पोस्ट

टोंक। सीआईएसएफ जवान ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। तीन दिन पहले ही वह छुट्टियां लेकर घर आया था। तीन महीने पहले जवान की शादी हुई थी। पत्नी 5 दिन ही ससुराल में रही थी। उसके बाद से जवान के ससुराल वाले पत्नी को नहीं भेज रहे थे। मामला टोंक के सोप में गांव कल्याणपुरा का रविवार रात 2 बजे का है। जवान की वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बिलाई में पोस्टिंग थी। थाना प्रभारी राजेश तिवाड़ी ने बताया कि सुसाइड करने वाला सीआईएसएफ जवान सुरेश मीणा (32) पुत्र रामप्रसाद मीणा है। रविवार रात 11 बजे उसने बड़े भाई राकेश कुमार को कॉल किया था। राकेश खाटूश्यामजी गया था। सुरेश ने पूछा था कि भैया घर कितने बजे लौटोगे। राकेश ने कहा था, आ रहा हूँ एक दो बजे आ जाऊंगा। राकेश रात करीब दो बजे घर आया और सुरेश कमरे में गया तो वह पंखे से रस्सी के सहारे लटका मिला।



तनाव में नहीं था। अचानक उसने खुदकुशी कर ली। किस वजह से की, समझ नहीं आ रहा है। पुलिस मामले दर्ज कर जांच कर रही है।

दहेज में दी कार भी 15 दिन पहले ससुराल वाले ले गए थे

बड़े भाई राकेश कुमार ने बताया कि सुरेश की शादी अप्रैल में हुई थी। तब उसकी पत्नी चार-पांच दिन रही थी। उसके बाद वह पीहर गई तो नहीं लौटी। सुरेश के ससुराल वाले पता नहीं किस बात से नाराज थे कि उन्होंने फिर पत्नी को ससुराल नहीं भेजा। शादी में लड़की पक्ष की ओर से दहेज में दी गई स्विफ्ट डिजाइर कार को भी करीब 15 दिन पहले ले गए थे। इसकी जानकारी हमने सुरेश को भी दे दी थी। सुरेश ने कहा था कि कोई बात नहीं है। मैं कुछ दिन बाद घर आऊंगा। वहीं बैठकर इस पूरे मामले पर बात करेंगे।

तीन भाइयों में सबसे छोटा था

थाना प्रभारी तिवाड़ी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जवान को नीचे उतारकर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया- सुरेश तीन भाइयों में सबसे छोटा था। तीन माह पहले ही शादी हुई थी। परिजनों के अनुसार वह आया जब किसी तरह के

जिला जल एवं स्वच्छता समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित

जल जीवन मिशन के तहत मांडल बना शत प्रतिशत घरेलू जल कनेक्शन वाला राज्य का पहला ब्लॉक

द पुलिस पोस्ट

जिला कलक्टर ने जेजेएम के कार्य में प्रगति लाने के दिये निर्देश



भीलवाड़ा, ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन के तहत जिले में सफल क्रियान्वयन के लिये जिला जल एवं स्वच्छता समिति की मासिक समीक्षा बैठक जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्टर सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जन स्वा.अभि.विभाग के कार्यवाहक अधीक्षक अभियन्ता किशन खोईवाल ने जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में अवगत करवाया एवं अधिशाषी अभियन्ता बी.एस. नकलक ने चल रही/निर्माणधीन कार्य योजना, कार्य की गुणवत्ता, डाटा अपडेशन एवं प्रगतिरत कार्यों से अवगत करवाया। जिला जल प्रयोगशाला के वरिष्ठ रसायनज्ञ इकबाल हुसैन ने जिले में हो रहे जल परीक्षण के बारे में अवगत करवाया। चम्बल प्रोजेक्ट के अधीक्षक अभियन्ता राजीव

कुमार ने पीपीटी के माध्यम से जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रही गतिविधियों का प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में अध्यक्ष ने जल जीवन मिशन के तहत माण्डल ब्लॉक में शत प्रतिशत घरेलू जल संबंध होने से राज्य में पहला हर घर जल वाला ब्लॉक घोषित होने पर विभाग की प्रगति की प्रशंसा की। जिला कलक्टर ने जेजेएम के कार्य में प्रगति लाने एवं माण्डलगढ़ ब्लॉक में शेष रहे घरों को अग्रस्त तक (आगामी बैठक) टैप कनेक्शन उपलब्ध

करवाए जाने के निर्देश दिये ताकि माण्डलगढ़ ब्लॉक जिले का द्वितीय सेचुरेटेड ब्लॉक बन सके। आसीन्द व बदनोर की प्रगति कम होने पर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। बैठक में अध्यक्ष ने आईएसएफ माया जन विकास सेवा संस्थान को निर्देश दिये कि वंचित ग्रामों में आगामी बैठक तक 100 प्रतिशत वाले ग्रामों को हर-घर जल प्रमाणीकरण करवाए एवं ग्राम सभाओं में हर घर जल प्रमाण पत्र जारी करवाने के भी निर्देश प्रदान किये। बैठक में उन्होने

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये कि जल संबंध से वंचित सभी स्कूल, आंगनबाडी, ग्राम पंचायत भवन एवं स्वास्थ्य केन्द्र की सूची विभाग को भेजकर सभी में जल संबंध करने के लिए निर्देशित किया। और जहां पाईप लाईन डालने पर रोड कटौत में खराब हुए रोड को ठीक करने के निर्देश दिये। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर रतन कुमार, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा गारू एवं योगेश पारीक, सीएमएचओ डॉ. सी.पी.गोस्वामी, अधीक्षक अभियन्ता एवीवीएनएल वी.के. संचेती, पशु पालन विभाग से डॉ. अरुण कुमार, अधिशाषी अभियन्ता निरंजन सिंह आढ़ा, सिद्धार्थ टांक, अशोक कुमार बैरवा, जिला कन्सल्टेंट डी.एस.यू. मुकेश कुमार शर्मा, डीपीएमयू से शशीकांत राव, कजोडमल जांजिड़, आईएसएफ के कमलेश, सत्यनाराण सैनी एवं जन स्वास्थ्य अभि. विभाग के सभी अभियन्ता सहित सम्बन्धित सदस्य और जिला पदाधिकारी मौजूद रहे।

बांध के पानी में दौड़ाई कार और बाइक 300 से ज्यादा मगरमच्छ के बीच जान जोखिम में डाली, वीडियो आया सामने



द पुलिस पोस्ट

अलवर। जिले से करीब 16 किमी दूर सिलीसेढ़ बांध में युवकों ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। सात युवक रील बनाने के चक्कर में बांध में कार और बाइक लेकर

पानी में उतर गए। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद सातों को गिरफ्तार किया गया। जिले में मंगलवार सुबह से घने बादल हैं। रात को भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। बरसात से बांधों में भी पानी आया है। लोग बांधों पर घूमने जा रहे हैं।

बांध में 300 से ज्यादा मगरमच्छ बांध इस समय करीब 18 फीट 9 इंच पानी है और करीब 300 से ज्यादा मगरमच्छ हैं। बांध में जिस तरह बोटिंग होती है। उस तरह मगरमच्छ कम होते हैं। युवक जिस तरह बाइक-कार लेकर गए। उस तरह मगरमच्छ ज्यादा है। सर्दियों के दिनों में तो मगरमच्छों

झुंड के झुंड धूप में पड़े नजर आते हैं। पुलिस ने सातों युवकों को पकड़ा पुलिस ने बांध में बाइक और कार चलाने वाले सातों युवकों को पकड़ है, जिसमें गुरुमेल सिंह (28) पुत्र सिंगारा सिंह निवासी सोरखा कला ततारपुर, योगेश (23) पुत्र सुरेंद्र निवासी सोरखाकला ततारपुर, कृष्ण (23) पुत्र धर्मचंद निवासी सोरखा कला ततारपुर, पुनीत (19) पुत्र सुभाष निवासी सारेखा कला ततारपुर, सचिन (27) पुत्र अशोक निवासी सोरखा कला ततारपुर, शिवचरण (29) पुत्र नरेश निवासी सोरखा कला ततारपुर और उदय (18) पुत्र हरीश निवासी बडौदामेव को गिरफ्तार किया

ग्रामीण हाट बाजार में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर 18 जुलाई को द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा, जिले के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने, औद्योगिक निवेशकों को बढ़ावा देने तथा उद्यमियों, नव उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए मार्ग दर्शन प्रदान करने हेतु तथा मौके पर योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने, आवेदन पत्र तैयार कराये जाने के लिए ग्रामीण हाट बाजार में 18 जुलाई को प्रातः 11 बजे औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित होगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक के.के. मीना ने बताया कि शिविर में डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, 2022, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, हस्तशिल्पियों, लघु उद्यमियों, दस्तकारों, बुनकरों के आई.डी. कार्ड (परिचय पत्र) एवं बीमा योजना साथ ही विपणन हेतु ग्रामीण हाट बाजार एवं उद्योग मेलों की जानकारी, औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपांतरण, आवंटन, एमएसएमई भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी दी जायेगी।

20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा बैठक 23 जुलाई को द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा, 20 सूत्री कार्यक्रम वर्ष 2024-25 की माह जून 2024 तक की प्रगति की समीक्षा हेतु द्वितीय स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में 23 जुलाई को दोपहर 12:15 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। यह जानकारी मुख्य आयोजना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (20 सूत्री कार्यक्रम) भंवर लाल आमेटा ने दी।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक साथ लगाए 2500 पौधे

सांसद श्री दामोदर अग्रवाल ने सभी को वृक्षारोपण करने और प्लास्टिक का पूर्ण बहिष्कार करने का संकल्प दिलाया

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मंशानुसार एक पेड़ माँ के नाम अभियान एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रोत्साहित मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान के अंतर्गत मंगलवार को जिला पर्यावरण समिति, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भीलवाड़ा और संकल्प पर्यावरण संस्थान भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में श्री महादेव मोक्षधाम, पटेल नगर में सघन वन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सांसद श्री दामोदर अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल और अधीक्षक वैज्ञानिक अधिकारी महेश सिंह कार्यक्रम में मंचस्थ थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दामोदर अग्रवाल ने उपस्थित जन समूह को पौधारोपण की महत्ता बताते हुए सभी अधिकारियों, विद्यार्थियों और जनप्रतिनिधियों से एक पेड़ माँ के नाम



अभियान के तहत सबको एक पौधा लगाने का संकल्प दिलाया। इसके अतिरिक्त माननीय सांसद महोदय ने सभी आमजन से प्लास्टिक का पूर्ण बहिष्कार करने व कपड़े का थैला उपयोग करने का भी संकल्प दिलाया। दीपक धनेटवाल ने भी उपस्थित जन समूह को विभाग द्वारा किए जा रहे



नवाचारों की सूचना भी दी। कार्यक्रम में 21 प्रकार के 2500 पौधों का सघन वन पौधारोपण करते हुए उनका संरक्षण करने का भी संकल्प किया गया। इस कार्यक्रम में भागशह के रूप में मैसर्स कृष्णा कॉन्टन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री भीलवाड़ा ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में राजस्थान राज्य प्रदूषण

नियंत्रण मंडल के सभी अधिकारी एम-कर्मचारी एवं संकल्प पर्यावरण संस्थान के सभी सदस्यों इत्यादि का सहयोग रहा। कार्यक्रम में वृक्षारोपण की शुरुआत एक पेड़ माँ के नाम मानव श्रृंखला बनाकर और राष्ट्रगीत गाकर की गई। पर्यावरण संरक्षण एवं सघन वन वृक्षारोपण कार्यक्रम में राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एवं प्रत्येक आंगतुक ने अभियान के तहत एक पौधा अपनी माँ के नाम पर समर्पित किया और बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। वृक्षारोपण के पश्चात सभी विद्यार्थियों एवं समस्त आंगतुकों को कपड़े के थैले एवं कैप वितरण की गई।

हरीश चौधरी बोले सरकार बचाने के लिए फोन टैपिंग अनैतिक: सचिन पायलट में नेतृत्व की क्षमता है, उनकी काबिलियत को सलाम



द पुलिस पोस्ट

चैनल को सोमवार को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही।

पायलट ने कभी सीएम बनने की बात नहीं की

हरीश चौधरी ने कहा- मीडिया ने भ्रम फैलाया, पायलट ने कभी मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं की। उन्होंने कभी प्रदेशाध्यक्ष या मंत्री बनने की भी बात नहीं की। उनकी छवि खराब करने के लिए सुनियोजित साजिश रची गई। पायलट ने तर्क के आधार पर यह डिमांड रखी थी कि उनके एमएलए और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सचिन पायलट राजस्थान के निर्माण के लिए अपने आपको झोका रहा है। पैदल चलना पड़ता है तो चल रहा है। वो सरकार के खिलाफ नहीं था, वो मुझे के आधार पर था। राहुल गांधी के अनुयायी हैं, नरेंद्र मोदी के अनुयायी नहीं हैं। कांग्रेस के अंदर रहने वाले लोग उनको आदर्श मानते हैं। हम लोग असली कांग्रेस हैं। यह सबको पता है कि कौन इस तरीके का गठजोड़ कर रहा है। मुझे के आधार पर राजनीति करो।

फोन टैपिंग बड़ा अनैतिक कृत्य, नेतृत्व योग्य नहीं

फोन टैपिंग पर चौधरी ने कहा कि अगर फोन टैपिंग हुआ है तो बड़ा अनैतिक है। जो व्यक्ति अनैतिक कृत्य करता है, वो व्यक्ति नेतृत्व के लिए योग्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, जिस किसी ने फोन टैप किया है। वो योग्य व्यक्ति नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि फोन टैपिंग हुई है या नहीं। फोन टैपिंग हुई है तो किसने की है, ये दोनों सवाल हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। गहलोत पर साधा निशाना- सीएम खुद छात्रसंघ चुनाव रोके, फिर कहे छात्र राजनीति मेरा प्यार छात्रसंघ चुनाव पर हरीश चौधरी ने कहा- मैंने अपनी सरकार के समय भी चुनाव करवाने की मांग उठाई थी। गहलोत जी ने चुनाव किस कारण नहीं करवाए, मुझे यह समझ में नहीं आया। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मैं छात्र राजनीति से आया हूँ। मेरा पहला प्यार उससे है। मैं मुख्यमंत्री रहूँ और छात्रसंघ चुनाव रोकूँ, फिर मैं कहीं मुझे छात्र राजनीति से प्यार है। यह फैसला प्यार नहीं

दिखा रहा है। मैंने उस वक्त भी कहा कि छात्रसंघ चुनाव को मत रोको। छात्रसंघ चुनाव करवाने से वोटों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। पता नहीं कौन सलाहकार थे। आज उसमें से कई सलाहकार बीजेपी की सरकार में हैं। वो सत्ता के इर्द-गिर्द रहने वाले लोग हैं। किसी से सलाह से किया है, वो मुझे पता नहीं है।

बीते 10 साल में सत्ता के विधायक के लिए सीबीआई को केस रेफर किया क्या

कमलेश एनकाउंटर में सीबीआई जांच की सिफारिश करने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम लिए बिना हरीश चौधरी ने निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि बीते 10 साल में किसी सरकार ने खुद के विधायक के लिए सीबीआई को केस रेफर किया है। यह पूरा अध्ययन करने की जरूरत है। मैंने जाकर उल्टा धन्यवाद दिया। जो लोग वहां गए, उनकी मंशा क्या थी, वह सार्वजनिक हो चुकी है। बाइमेर के दो व्यक्ति थे। उन्हें

गहलोत के जिले बनाने पर उठाए सवाल

हरीश चौधरी ने अपनी सरकार पर बात करते हुए कहा कि कई ऐसे फैसले हुए, जैसे-दूदू को जिला बना दिया, कोई व्यक्ति इस तर्क को स्वीकार करेगा क्या? केवल वाहवाही लेने के लिए यह किया। बायतु जिला बनाने का मुझे किसी ने कहा, अगर मैं बायतु को जिला बना दूँ तो तार्किक तौर पर सही था। कई ऐसे फैसले थे। हमारा संविधान क्या कहता है कॉलेबोरेटिव चीजें होनी चाहिए। भैरोसिंह शेखावत ने जिस दिन बिजनेस रूल्स में फेरबदल किया, उस दिन आगे बढ़ता राजस्थान टप हो गया। किसी मुख्यमंत्री ने फेरबदल नहीं किया, मैंने वो बात कई बार उठाई।

राजस्थान के अनुरूप नहीं हो रहे फैसले

बजट पर बोलते हुए हरीश चौधरी ने कहा- राजस्थान में सरकार ही नहीं है। यह पूरा राजस्थान जानता है। सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये फैसले कौन ले रहा है, यह सब जानते हैं। धरातल पर जनता को जो चीज चाहिए थी, वो इस बजट में नहीं थी। जब से यह सरकार बनी है। जो फैसले हो रहे हैं, राजस्थान के धरातल के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है।

बेवजह फंसाने के लिए बाइमेर के दो व्यक्ति को कोई दबा नहीं सकता है। अगर मैं गलत हूँ। बीच रास्ते में चलता व्यक्ति भी कह सकता है कि आप गलत हो। मैं उससे भी माफी मांग लूंगा।

धूमधाम से मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला कलेक्टर ने विभागों को तैयारियों के निर्देश दिए

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा, स्वाधीनता दिवस समारोह (15 अगस्त) धूमधाम से उत्सव की तरह मनाया जायेगा। शहर के मुख्य चौराहों और सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया जायेगा। आजादी के पर्व पर मुख्य समारोह पुलिस लाइन में आयोजित किया जायेगा। मुख्य समारोह स्थल पर झंडारोहण सुबह 9 बजकर 5 मिनट पर किया जायेगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रम से पूर्व सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।



जायेंगे। इसके लिए सचिव, नगर विकास न्यास को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य समारोह स्थल के अंदर ग्राउंड में पर्याप्त मात्रा में ध्वज लगाये जायेंगे। मुख्य समारोह स्थल पर मंच की व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर विकास न्यास को सौंपी गई है। समारोह स्थल पर आंगतुकों के लिए कुर्सियों, दरियों, शामियाना, कनात, छाया-पानी, टॉयलेट आदि की व्यवस्था नगर परिषद एवं नगर

प्रतिभाओं के लिए प्रशस्ति पत्र मय फ्रेम पुरस्कार एवं मेडल की व्यवस्था तथा मार्च पास्ट एवं बैंड प्रदर्शन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार की जिम्मेदारी नगर विकास न्यास की होगी। इसी के साथ स्वतंत्रता सेनानियों/शाहीद सैनिकों की वीरगंगाओं को समारोह स्थल तक लाने एवं ले जाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान हेतु उच्च कोटि की शॉल, श्रीफल आदि की व्यवस्था यूआईटी द्वारा की जायेगी। रिहर्सल के दौरान मुख्य समारोह दिवस तक प्राथमिक चिकित्सा के लिए ए श्रेणी के कम्पाउण्डर एवं आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था पीएमओ द्वारा की जायेगी। समारोह के दौरान ए श्रेणी चिकित्सा दल मय एम्बुलेंस समारोह स्थल पर मौजूद रहेगा। मार्च पास्ट एवं बैंड प्रदर्शन के लिए प्रतिभागियों के लिए पूर्वाभ्यास के दौरान 12

अगस्त से परिवहन व्यवस्था जिला परिवहन अधिकारी व मुख्य समारोह में व्यायाम प्रदर्शन, परेड आदि कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं एवं अन्य के लिए मिठाई की व्यवस्था जिला रसद अधिकारी द्वारा की जायेगी।

पूर्व संध्या पर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को शाम 6.30 बजे से टाउनहाल, नगर परिषद में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी अपनी प्रस्तुति देंगे। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) रतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) वंदना खोरवाल, एसडीएम आवहाद नि सोमनाथ, यूआईटी ओएसडी मोहम्मद ताहिर सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर में जन्मदिन पर स्विमिंग पूल में डूबा बच्चा, मौत

बर्थडे की खुशी में दोस्तों के साथ नहाने गया था, एक साल में तीसरी मौत

द पुलिस पोस्ट

जयपुर। जयपुर में 14 साल के बच्चे की उसके जन्मदिन के दिन ही स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। मृतक अविनाश यादव जन्मदिन की खुशी में अपने दोस्तों के साथ पूल पर गया था। जब दोस्तों को अविनाश नहीं दिखा तो उन्होंने गार्ड को जानकारी भी दी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। काफी देर दूढ़ने के बाद बच्चा आखिर पूल में ही डूबा मिला। अविनाश की मौत के बाद बड़े भाई अमरनाथ कुमार (19) ने स्विमिंग पूल मालिक के खिलाफ मानसरोवर थाने में 15 जुलाई को केस दर्ज करवाया है। बता दें कि इस पूल में एक साल में ये तीसरी मौत है। अमरनाथ यादव ने पुलिस को दी रिपोर्ट में कहा कि 14 जुलाई को उसके छोटे भाई अविनाश यादव का 14वां जन्मदिन था। सुबह 10 बजे मां से 100 रुपए लेकर गया था। उसने बताया था कि कॉलोनी के दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में जा रहा है। वह करीब 10.30 बजे मानसरोवर स्थित एसआर स्विमिंग पूल पर पहुंचा था। पूल पर पहुंचने के कुछ देर बाद अविनाश गायब हो गया। इस दौरान साथ गए बच्चों ने पूल के बाहर खड़े गार्ड को बताया- अविनाश दिख नहीं रहा। इस पर गार्ड ने बच्चों को बाहर देख कर आने के लिए बोला। बच्चे बाहर गए, लेकिन अविनाश नहीं मिला। बच्चों ने दोबारा गार्ड को बोला अविनाश नहीं मिल रहा। इस पर गार्ड ने बाथरूम में देखने को कहा।

सभी जगह दूढ़ते रहे, आखिर में पूल के अंदर डूबा मिला

सभी जगह देखने के बाद अविनाश नहीं मिला तो गार्ड ने पूल में देखा। करीब 11 बजे अविनाश पानी में डूबा दिखाई दिया। इस पर अविनाश को बाहर निकाला गया और तुरंत धनवंतरी हॉस्पिटल लेकर गए। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच अमरनाथ यादव के एक दोस्त गोविंदा ने यह पूरा घटनाक्रम देख परिवार को सूचित किया।

बच्चे को स्विमिंग नहीं आती थी, फिर भी कोच नहीं था

अमरनाथ ने बताया कि अविनाश को स्विमिंग नहीं आती थी। स्विमिंग पूल मालिक की ओर से पूल के आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हुए थे। जिस पूल में बच्चों को जाने की परमिशन दी गई, वहां 7 फीट तक पानी भरा हुआ था। स्विमिंग पूल के आसपास स्विमिंग कोच नहीं था। अमरनाथ ने कहा कि अविनाश जब डूबा तो उसे किसी ने नहीं देखा। अविनाश को किसी ने पानी में संघर्ष करते हुए भी नहीं देखा। जो हो नहीं सकता है। इस घटना में पूरी लापरवाही स्विमिंग पूल मालिक की है। अमरनाथ और अविनाश दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। पिता प्लंबर का काम करते हैं। मां लोगों के घरों में सफाई करती हैं। इस घटना के बाद माता-पिता का रो-रो कर बुरा हाल है।

बुजुर्ग महिला से लूट: घर के पास बदमाशों ने किया हमला, चैन तोड़ते समय गले में लगी चोट

जयपुर ।

जयपुर में बुजुर्ग महिला से लूट का मामला सामने आया है। घर के पास बदमाशों ने हमला कर चैन तोड़ ली। चैन स्नेचिंग के दौरान बुजुर्ग महिला के गले में चोट लग गई। बजाज नगर थाने में पीड़िता के पति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। SI रामोतार ने बताया- जय जवान कॉलोनी द्वितीय निवासी रामदयाल गौयल (64) ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनकी पत्नी के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात की। सुबह करीब 7 बजे उनकी पत्नी गौशाला से वापस घर लौट रही थी। घर से कुछ दूरी पर बाइक सवार दो बदमाशों ने पीछे से हमला किया। गले पर झपट्टा मारकर बदमाशों ने सोने की चैन तोड़ ली। शोर मचाकर पीछा करने पर बदमाश तेजी से बाइक लेकर फरार हो गए। छीना-झपट्टी के दौरान गले में चोट आने से वह घायल हो गई। पुलिस वारदातस्थल के आस-पास लगे CCTV फुटेजों को खंगालने के साथ बाइक सवार लुटेरों की तलाश कर रही है।



जयपुर समेत 5 शहरों में घर खरीदने की तारीख बड़ी

648 मकानों के लिए 15 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन, 12 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कीमत

जयपुर।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 5 शहरों में लॉन्च की आवासीय स्कीम में आवेदन की आखिरी तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। ये चौथा मौका है, जब बोर्ड के पास पर्याप्त आवेदन नहीं आए, जिसे देखते हुए आवेदन की अंतिम तारीख को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया। हाउसिंग बोर्ड की ओर से मार्च में 9 अलग-अलग शहरों में आवासीय योजना लॉन्च करके आवेदन मांगे थे, जिसमें से धौलपुर के बाड़ी में 13 आवेदन, जयपुर के प्रताप नगर 336, अलवर के पास भिवाड़ी में 15, अजमेर के पास किशनगढ़ में खोड़ा गणेश योजना के 104 और हनुमानगढ़ के न्यू आवासीय योजना



अगस्त में निकलेगी योजनाओं के आवेदनों की लॉटरी

इन मकानों के आवेदन मिलने के बाद इनकी लॉटरी अगस्त के आखिरी सप्ताह तक निकाली जा सकती है। सबसे ज्यादा आवेदन उदयपुर की गोवर्धन विला स्कीम में आए हैं। यहां करीब 200 मकानों के लिए 23 हजार से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। इसी तरह माउंट आबू, जयपुर की वाटिका, जोधपुर की बड़ली और नागौर की योजना के आवेदनों की भी लॉटरी निकाली जाएगी। जोधपुर के बड़ली में करीब 1090 मकान तैयार करवाए जाएंगे। इनकी लॉटरी भी इसके साथ निकाली जाएगी। ऐसे में इन सभी 9 शहरों 3001 फ्लैट और मकानों की लॉटरी की तैयारी की जा रही है।

डीटीओ में 180 आवासों के लिए आवेदनों की संख्या कम आई है। बोर्ड ने अप्रैल, मई के बाद जून में भी एक माह की तारीख बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों का रुझान इन मकानों को लेकर कम है। इसे कारण इन योजनाओं में आवासों की संख्या जितने भी आवेदन नहीं आए। इसे देखते हुए बोर्ड प्रशासन ने एक बार फिर से इन योजनाओं में आवेदन की तारीख को 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।

सिर तन से जुदा नारे लगाने वाले लोग बरी

2 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, अजमेर दरगाह के बाहर लगाए थे नारे

अजमेर ।

अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ में सिर तन से जुदा नारे लगाने के मामले में आज फैसला आया है। खामिद सहित सभी छह आरोपियों को एडीजे-4 कोर्ट ने बरी कर दिया है। पूरे प्रकरण को लेकर 2 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। इस दौरान 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे।

वर्ष 2023 में दरगाह थाने में हुआ था मुकदमा दर्ज

सरकारी वकील गुलाम नजमी फारूकी ने बताया- जून 2022 में दरगाह की सीड़ियों पर सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे। मामले में खामिद गौहर चिशती, अजमेर के रहने वाले ताजिम सिद्दीकी (31) पुत्र नईम खान, फखर जमाली

(42) पुत्र सैयद मोहम्मद जुबैर जमाली, रियाज हसन दल (47) पुत्र हसन, मोईन खान (48) पुत्र स्व. शमसुद्दीन खान, नासिर खान (45) आरोपी थे। जज रितु मीणा की कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। इस मामले में एक आरोपी अहसानुल्लाह फरार है। उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया है।

दुर्लभ बीमारी वाले बच्चों को हर महीने 5 हजार देंगे : दीया कुमारी

500 छात्राओं को मिलेगी स्कूटी; किसानों को 30 फीसदी ज्यादा मुआवजा

जयपुर।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने घोषणा की है कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। इसके साथ ही बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के लिए उन्हें 30

फीसदी ज्यादा मुआवजा मिलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार हर साल पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाली 500 छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी। दीया कुमारी मंगलवार को विधानसभा में बजट बहस पर जवाब दे रही थीं। दीया कुमारी ने कहा कि बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाली किसानों की जमीनों का डीएलसी की दर से 30 फीसदी ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। बिजली के ट्रांसमिशन टावर के लिए किसानों की जमीन का डीएलसी

रामलला के दर्शन कराएगी सरकार

राज्य सरकार स्पेशल ट्रेन चलाएगी, इस ट्रेन के जरिए राजस्थान के लोग अयोध्या में राम लला के दर्शन करने जा सकेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। अब तक इस योजना में केंद्र सरकार 5 हजार रुपए दे रही थी। माना जा रहा है कि राज्य सरकार 5 हजार रुपए अपनी तरफ जोड़कर महिलाओं के खतों में यह पैसा डालेगी।

दर से दोगुना मुआवजा मिलेगा। मीटर एक्स्ट्रा जमीन की गणनाकर ट्रांसमिशन टावर के चारों तरफ एक मुआवजा दिया जाएगा।

जयपुर में खुलेगी कृषि उपज मंडी

सीकर रोड पर जैतपुरा से जयसिंहपुरा तक बनेगा हाईवे; बजट रिप्लाइ पर वित्तमंत्री ने की घोषणा

जयपुर।

बजट के रिप्लाइ पर घोषणा करते हुए वित्तमंत्री दीया कुमारी ने आज जयपुर में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेन्द्र खोलने की घोषणा की है। इस सेंटर को खोलने से राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की उपग्रह के जरिए रिमोट टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। इसके साथ ही प्रदेश में नए खनिजों की खोज, शहरों सर्वे, वन एवं पर्यावरण सम्पदा पर निगरानी भी की जा सकेगी। वित्त मंत्री ने इस केन्द्र के अलावा जयपुर में सीकर रोड पर जैतपुरा से जयसिंहपुरा तक 16 किलोमीटर बाइपास बनाने का भी ऐलान किया। इस पर करीब 130 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा



जयपुर के दिल्ली बाइपास स्थित तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा का विकास कार्य करवाया जाएगा। इसी के साथ चैम्पू के जैतपुरा में नई पीएचसी और कोटखावदा में नई कृषि उपज मंडी खोलने की भी घोषणा अपने रिप्लाइ के दौरान की।

लिफ्ट ट्रॉली टूटकर मजदूर पर गिरी, मौत

जयपुर।

जयपुर में एक मकान की चौथी मंजिल पर निर्माण काम के दौरान मंगलवार दोपहर लिफ्ट ट्रॉली टूट गई। 300 चत वजनी ट्रॉली नीचे खड़े मजदूर के ऊपर गिरने से उसकी मौत हो गई। लोगों ने क्षत-विक्षत हालत में शव को ट्रॉली के नीचे से बाहर निकाला। रामगंज थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को SMS हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी भिजवाया।

SHO (रामगंज) उदय सिंह यादव ने बताया- हादसे में रिकब (24) निवासी पेंटर कॉलोनी भद्रबस्ती की मौत हो गई। मंगलवार सुबह वह अपने छह-सात साथियों के साथ जियाउद्दीन कॉलोनी में एक मकान की चौथी मंजिल पर निर्माण काम के लिए आया था। दोपहर करीब 3 बजे लिफ्ट ट्रॉली से बजरी-

चौथे फ्लोर पर चढ़ाया जा रहा था सामान, 300 KG के नीचे दबने से शव बिखरा



रोड़ी 4 फ्लोर पर चढ़ाई जा रही थी। रिकब नीचे खड़े होकर सामान को लोड कर ट्रॉली से ऊपर भेज रहा था।

ट्रॉली से सामान चढ़ाते समय अचानक लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट टूटते ही करीब 300 चत वजनी ट्रॉली नीचे खड़े मजदूर रिकब पर आकर गिरी। मजदूर के ऊपर ट्रॉली गिरने का पता चलने पर हड़कम्प मच गया। स्थानीय लोगों ने साथी मजदूरों के साथ मिलकर तुरंत ट्रॉली के नीचे से क्षत-विक्षत हालत में शव को बाहर निकाला गया। रामगंज थाना पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव स्वरू हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी भिजवाया।

800 किलो खराब पनीर नष्ट कराया

हरियाणा के नूह से राजस्थान लाया जा रहा था; चैकिंग के दौरान पकड़ी गाड़ी, 3 गिरफ्तार

जयपुर।

फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने पुलिस की मदद से जयपुर के विराटनगर एरिया में खराब पनीर की बड़ी खैप पकड़ी। पनीर में बदबू आने और प्रथम दृश्य देखने में खराब मिलने पर टीम ने मौके पर 800 किलोग्राम पनीर को नष्ट करवाया। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनकी गाड़ी को जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया- हरियाणा के नूह से एक पिकअप में तीन लोगों के राजस्थान में आने और उसमें घटिया पनीर लाने की



सूचना मिली थी। इस पर विराटनगर डिप्टी के नेतृत्व में भाबर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकेबंदी की। नाकेबंदी के पास जैसे ही गाड़ी पहुंची तो

टीम ने मौके पर जब पनीर की जांच की तो वह दिखने में हल्का पीला था और उसमें से बदबू भी आ रही थी। इसके अलावा पनीर को हाथ से तोड़ने पर वह रबड़ की तरह लिख रहा था। इस पर टीम ने पनीर के सैंपल लेकर मौके पर ही गाड़ी में अलग-अलग डिब्बों में भरा 800 किलोग्राम पनीर को नष्ट करवाया। वहीं पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान मौके पर पिकअप को जब्त किया और उसमें सवार तीन लोग आजाद, अरशद व अशफाक को गिरफ्तार में लिया।

ट्रक और कार की टक्कर में 8 घायल

इंदौर का परिवार खाटूश्याम के दर्शन कर वापस लौट रहा था

जयपुर।

जयपुर में सुबह 6 बजे कार और ट्रक की टक्कर में आठ लोग घायल हो गए। घटना रेनवाल जोबनेर सड़क मार्ग पर हुई। प्राथमिक उपचार के बाद गम्भीर रूप से घायल हुए दो घायलों को डॉक्टर ने जयपुर रेफर कर दिया। जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जयपुर एम्सएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

दुर्घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे एम्सआई प्रह्लाद बाजिया ने बताया- कार में आठ लोग सवार थे। जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। खाटूश्याम के दर्शन करके मध्य प्रदेश लौट रहे थे। रेनवाल जोबनेर मुख्य सड़क पर सामने से आ रहे ट्रक और कार में भिड़ंत हो



गई। इसमें कार सवार आठ लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें तत्काल 108 एम्बुलेंस की सहायता से रेनवाल उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो घायलों की तबीयत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टर ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया है। घायलों में मध्य प्रदेश में इंदौर के रहने वाले योगेश कुमार (32), मंजू बाई (60), सुधीर कुमार (22), शरुणु बाई

(64), कविता बाई (38), रीता बाई (42), पायल (20), विवेक कुमार (18) वर्ष शामिल थे। पुलिस ने इनके परिजनों को दुर्घटना की जानकारी दे दी है। हालांकि मंजू बाई और कविता बाई के अलावा सभी को सामान्य चोट लगी है। जिनका रेनवाल उप जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। दर्शन कर वापस लौट रहे थे

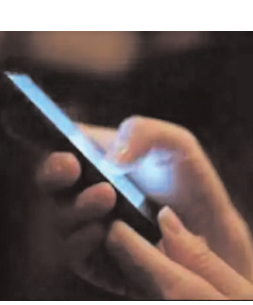
प्रारम्भिक पृष्ठताछ में सामने आया है कि ये सभी लोग 14 तारीख को एमपी इंदौर से खाटूश्याम दर्शन के लिए निकले थे। आज सुबह ही ये लोग जल्द एमपी के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन रास्ते में दुर्घटना होने और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर इन्हें स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। परिजनों को दुर्घटना की जानकारी दे दी गई है।

एक क्लिक से अकाउंट खाली, 3 लाख निकाले

महिला ने कॉल कर भेजा लिंक, मोबाइल पर मैसेज आने पर चला पता

जयपुर।

जयपुर में साइबर क्रिमिनल के एक क्लिक करवाकर 3 लाख रुपए अकाउंट से निकालकर ठगने का मामला सामने आया है। महिला ने कॉल कर धोखे से क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए लिंक भेजा था। मोबाइल पर मैसेज आने पर अकाउंट खाली होने पर साइबर फॉड का पता चला। मालवीय नगर थाने में पीड़ित ने साइबर फॉड का मामला दर्ज करवाया है। ASI जगाम ने बताया- मालवीय नगर के सेक्टर-1 निवासी अमित मल्होत्रा (41) के साथ साइबर फॉड हुआ है। दोपहर करीब 3 बजे उनके मोबाइल पर एक लड़की का कॉल आया। कॉल करने वाली लड़की ने खुद का नाम स्नेहा शर्मा बताकर इंडसट्री बैंक से बोलना बताया। क्रेडिट कार्ड पर सालाना 2499 रुपए की प्रोटेक्शन मनी लगाने की जानकारी दी। लाइफ टाइम फ्री बताकर दिए कार्ड को पीड़ित ने बंद करने के लिए कहा। बैंककर्मी बनकर बात कर रही स्नेहा ने क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए मोबाइल पर एक लिंक शेयर किया। लिंक पर क्लिक करने पर कार्ड डी-एक्टिवेट (बंद) हो जाना बताया। मोबाइल पर आए लिंक पर क्लिक करते ही 2.95 लाख रुपए अकाउंट से निकल गए। मोबाइल पर रुपए निकलने का मैसेज आने पर साइबर फॉड होने का पता चला। मालवीय नगर थाने में पीड़ित ने मोबाइल नंबर के आधार पर शिकायत दर्ज करवाई।



बीजेपी विधायकों को मिलेगी जनता से संवाद की ट्रेनिंग

जयपुर।

विधानसभा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायकों को जनता से कैसे संवाद किया जाए। इसे लेकर ट्रेनिंग देने की संज्ञा जताई।

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा- क्षेत्र में विधायक को ही सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना होता है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि विधायक जनता से संवाद बनाए रखें। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि विधायक और उनके स्टॉफ को जनता से शालीनता से पेश आना चाहिए। सभी विधायक क्षेत्र के लोगों के फोन भी अटेंड करें। उन्हें तुरंत रिप्लाइ भी करें। बता दें कि विधानसभा की हॉ पक्ष लॉबी में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत में सभी विधायकों ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए ताली बजाकर सीएम भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया।

विधानसभा सत्र के बाद आयोजित होगा ट्रेनिंग सेशन

विधायकों का ट्रेनिंग सेशन मौजूदा विधानसभा सत्र के बाद आयोजित हो सकता है। विधायकों को ट्रेनिंग को लेकर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- सीएम भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि सभी विधायक सदन के नियम और प्रक्रिया में परांपरा हो। सदन की स्वस्थ परंपरा को उन्हें जानकारी हो। इसके साथ ही विधायक, उनका ड्राइवर,



गनमैन और अन्य स्टॉफ जनता के साथ शालीनता से पेश आए। जनता की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका समाधान करें। इसे लेकर विधायकों को ट्रेनिंग देने पर विचार चल रहा है। जोगाराम पटेल ने कहा- यह ट्रेनिंग सेशन मौजूदा सत्र के बाद आयोजित हो सकता है। जानकारी है कि विधायक दल की बैठक में कई विधायकों ने जयपुर अथवा राज्य के बाहर ट्रेनिंग सेशन आयोजित करने का सुझाव दिया है। वहीं, कुछ विधायकों का यह भी सुझाव था कि ट्रेनिंग सेशन में पूरी तरह से मोबाइल बने रहें।

विधायक ही करवाएंगे बजट का 100 प्रतिशत क्रियान्वयन

विधायक दल की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा- राज्य सरकार

ने प्रदेश के हर व्यक्ति और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट बनाया है। लेकिन बजट का शत प्रतिशत क्रियान्वयन आपके माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए आपके क्षेत्र की बजट घोषणाओं को लागू करवाने में आप अपना योगदान सुनिश्चित करें। सीएम भजनलाल ने कहा कि बजट घोषणाएं धरातल पर उतरें। उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। दो या उससे अधिक विभागों के बीच की योजनाओं को समन्वय समिति के माध्यम से पूरा करवाएं। वहीं प्रदेश स्तर की घोषणाओं के लिए प्रदेश स्तर पर सक्रिय रहें। विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को एकमुखी होकर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने के लिए भी कहा गया है। इसे लेकर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि हमने विधायक दल की बैठक में तय किया है कि हमारे सभी विधायक विधानसभा में विपक्ष के सकारात्मक सुझाव, आक्षेप और आरोप आते हैं, तो उसका जवाब देंगे। वहीं अगर विपक्ष व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसका उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा।

गन कल्चर ने बढ़ाई चिंता : अमेरिका में खिलौने की तरह मिलती है एआर-15 राइफल

वॉशिंगटन । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने एक बार फिर अमेरिका में गन कल्चर पर चिंता बढ़ा दी है। खयाल है कि एआर-15-स्टाइल राइफल अमेरिका में सबसे लोकप्रिय बंदूकों में से एक है। हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका में आए दिन गोलीबारी में इस बंदूक का ही उपयोग किया जाता है। बता दें कि यह अमेरिका में खिलौने की तरह मिलती है। एआर-15 अर्सेल?ट राइफल से हमला किया गया, उसे काफी खतरनाक माना जाता है। इस हमले के बाद सीक्रेट एजेंट और ट्रंप के सुरक्षा घेरे को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अगर किसी को एआर-15 राइफल से निकली गोली लग जाए, तो उसका बचना असंभव हो जाता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में हैंडगन प्रति वर्ष अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, एआर-15 का अवसर हाई-प्रोफाइल सामूहिक गोलीबारी में उपयोग किया जाता है। अमेरिका में एआर-15 खरीदना आसान है। राज्य के आधार पर, एक रजिस्ट्रार मालिक बंदूक की दुकान में जा सकता है और एक वैध आईडी प्रस्तुत करने के बाद, एक राइफल या शॉटगन खरीद सकता है। बशर्त कि वे संघीय पृष्ठभूमि जांच पास कर सकें। यह प्रक्रिया खरीदार के आपराधिक इतिहास को देखती है या यह देखती है कि क्या वे कभी मानसिक संस्थान में गए हैं। लेकिन निजी बिक्री के मामले में इस सरसरी जांच को भी दरकिनार किया जा सकता है। एआर-15 एक सेमी ऑटोमैटिक हथियार है, जिसका अर्थ है कि इससे एक के बाद एक कई शॉट फायर किया जा सकता है। इसके चचेरे भाई, एम-16 का उपयोग वियतनाम के बाद से अमेरिकी सेना द्वारा किया जाता रहा है। जबकि कुछ सैन्य अर्सेल राइफल पूरी तरह से स्वचालित हैं, अधिकांश परिस्थितियों में नागरिकों को ऐसे हथियार रखने से प्रतिबंधित किया जाता है।

एएसआई ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को कार से घसीटा, मुफ्त में भरना चाहता था पेट्रोल

-वीडियो वायरल होने के बाद हुआ सस्पेंड, पुलिस ने किया गिरफ्तार

कुन्नूर। मुफ्त में कोई चीज मिलने की बामारी लगभग सभी में होती है। किसी को इसकी आदत पड़ जाती है। गाड़ी में मुफ्त को पेट्रोल लेने का चरका सिर्फ पुलिसवालों को नहीं है। केरल के कुन्नूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक गाड़ी पेट्रोल पंप कर्मचारी को कुचलने की कोशिश कर रही है। बताया जाता है कि पेट्रोल के पैसे मांगने पर पंप कर्मचारी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करने वाला कुन्नूर पुलिस का एएसआई है। गनीमत यह रही कि कर्मचारी कार के धक्के के बाद बोनट पर ही गिर गया। आरोप है कि एएसआई ने कर्मचारी को धक्का मारने के बाद गाड़ी नहीं रोकी और बोनट में फंसे युवक को लेकर हाइवे पर गाड़ी दौड़ा रहा। अब आरोपी एएसआई के खिलाफ एएसआई के प्रयास का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि आरोपी एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो रविवार का है। जब कुन्नूर पुलिस का एएसआई के. संतोष कुमार (50) गाड़ी में पेट्रोल भरवाने पंप पर पहुंचा। वहां पेट्रोल पंप कर्मचारी अनिल ने गाड़ी में पेट्रोल भर दिया। जब पैसे मांगे तो एएसआई कार लेकर जाना लगा। पैसे को लेकर दोनों में कुछ देर बहस हुई। वीडियो में दिख रहा है कि अनिल ने गाड़ी के सामने आकर संतोष को रोकने की कोशिश की। एएसआई ने कार का इंजन चालू कर आगे बढ़ा दी, जिससे अनिल बोनट पर गिर गया। उसके हाथ में चोट लगी है। इसके बाद भी संतोष कुमार ने बोनट पर अटक के अनिल को लेकर एक किलोमीटर गाड़ी चलाई। अनिल ने इसकी शिकायत पुलिस की सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद कुन्नूर पुलिस ने एएसआई पर कारवाई की। कुन्नूर शहर के पुलिस आयुक्त अनिल कुमार ने बताया कि आरोपी एएसआई के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई धाराएं लगाई गई हैं और उसे निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि सोमवार को उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

2023 में 6 लाख बच्चों को टीका नहीं लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बना भारत

नई दिल्ली। भारत में 2023 में एक भी बच्चे को कोई सा टीका नहीं लगा है। ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश भारत बन गया है। यहां 16 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोई भी टीका नहीं लगा है। पहले नंबर पर नाइजीरिया है जहां ऐसे बच्चों की संख्या 21 लाख है। यह जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट से मिली है। इस रिपोर्ट में देशों की ओर से 1 जुलाई, 2024 तक दी गई जानकारी के आधार पर साल 2023 के लिए टीकाकरण कवरेज का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट के लिए विश्व बैंक के 2024 के डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग के 2024 के आंकड़ों का भी इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिना किसी टीके वाले बच्चों की संख्या पिछले साल के मुकाबले थोड़ी बढ़ी है। अब ऐसे बच्चों की संख्या 1 करोड़ 39 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 45 लाख हो गई है। यह संख्या साल 2019 के मुकाबले भी 17 लाख ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ बच्चों को पहला टीका लगाने के बाद तीसरा टीका नहीं लग पाया है। इस तरह बिना टीका या अर्ध-टीके वाले बच्चों की कुल संख्या 2023 में 2 करोड़ 10 लाख हो गई है जो पहले के आंकड़े से 27 लाख ज्यादा है। भारत में बिना खसरे का टीका लगाने वाले बच्चों की संख्या भी तीसरे नंबर पर है। ऐसे बच्चों की संख्या 16 लाख है। पहले और दूसरे नंबर पर नाइजीरिया (28 लाख) और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (20 लाख) है।

पाकिस्तान की गोद में बैठा हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी, कश्मीर पर उगल रहा जहर

नई दिल्ली। हिजबुल मुजाहिदीन का मकसद कश्मीर में एक इस्लामी राज्य बनाना है और जम्मू-कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करना है। इस आतंकी संगठन ने कश्मीर में खूब खून-खराबे किए हैं। 1990 के दशक में कई आतंकी हमलों और नगरों और सुरक्षाकर्मियों की हत्याओं, बम विस्फोटों और राजनीतिक नेताओं की हत्याओं को अंजाम दे चुका है। इसके लिए आए दिन आतंकी कारगराना हरकतें करते रहते हैं। कश्मीरियों को भड़काते हैं उन्हें लालच देते हैं और अपनी आतंकी दुकान चलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के आतंकियों का यह इंटरव्यू दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान चिकनी-चुपड़ी बातें करता है, मगर पीठ पीछे वह आतंकीवाद को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान या फिर उसके कब्जे वाले कश्मीर में बैटकर हिजबुल के कमांडर शमशीर खान ने एक डिजिटल चैनल को जेके बोल को अपना इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में हिजबुल कमांडर शमशीर खान कश्मीर पर जहर उगल रहा है। अभी जगह कन्फर्म नहीं है। वह कहता है कि हिजबुल मुजाहिदीन का मकसद भारतीय सेना का डटकर मुकाबला करना है और उन्हें चैन से नहीं बैठने देना है। शमशीर खान ने उस बात का भी जिक्र किया कि कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी को हीरो बताया था। बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन एक आतंकी संगठन है। इसे भारत समेत दुनिया के कई देश आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के डिटी सुप्रीम कमांडर शमशीर खान का यह इंटरव्यू ऐसे वक्त में आया है, जब जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले तेज हो गए हैं। हाल ही में आतंकियों ने कडआ में हमला किया था, जिसमें भारतीय सेना के पांच जवान शहीद हो गए थे। इससे पहले माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही एक बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। उस आतंकी हमले में नौ लोगों की मौत हो गई थी और 41 घायल हो गए थे।

बाबा पर लगा देवी कुंड को स्विमिंग पूल बनाने का आरोप

बागेश्वर। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सुंदरदुर्गा में सरकारी जमीन हड़पने का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक बाबा ने ग्लेशियर पर चोरी-छिपे मंदिर बना डाला। इस बाबा का नाम योगी चैतन्य आकाश है और उनका दावा है कि देवी भगवती उनके सामने में आई थीं और पहाड़ों पर 5,000 मीटर (16,500 फीट) से ज्यादा की ऊंचाई पर मंदिर बना का आदेश दिया था। योगी चैतन्य के इस दावे पर वहां पास के ही गांव में रहने वाले लोग भी सवाल उठाते हैं। इसी में एक महेंद्र सिंह धामी भी हैं, जिन्होंने बाबा पर देवी कुंड को अपवित्र करने का आरोप लगाया है। वहीं एक और शख्स प्रकाश कुमार कहते हैं, 'ये तो ईशान्ति है। सदियों से हर 12 साल में नंदा राज यात्रा के दौरान देवी-देवता देवी कुंड में आते हैं। इस बाबा ने लोगों को गुमराह करके हमारी परंपराओं के खिलाफ ये मंदिर बना डाला है।' गांववालों की इन आपत्तियों के बाद अब प्रशासन की भी नौद खुली है और उन्होंने इस अवैध निर्माण की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, कपकोट के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट अनुराग आर्य ने बताया कि वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग के कुछ लोग जल्द ही देवी कुंड जाएंगे। अतिक्रमण हटकर योगी चैतन्य के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, 'इस इंस बार में अभी पता चला है।' वहीं ग्लेशियर रेंज के रेंजर एनडी पांडे ने बताया, 'हमें इस बारे में जानकारी मिली है।

केरल में भारी बारिश से मची तबाही, दीवार गिरने से मां-बेटे की मौत

पलक्कड़। केरल में भारी बारिश से पलक्कड़ जिले में एक मकान की दीवार ढहने से मां और बेटे की मौत हो गई। मध्य और उत्तरी केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण घर की दीवार गिरने से मां और बेटे की मौत हो गई है। इस बारिश ने राज्य में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। यह घटना पलक्कड़ जिले के वडकनचेरी ताला क्षेत्र के कोट्टेक्कड़ में हुई है। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान सुलोचना और उनके बेटे रंजीत के रूप में हुई है। यह घटना जब घटी जब मां और बेटा सो रहे थे तो उनके पुराने घर की दीवार उनके ऊपर गिर गई, जिसमें दोनों दब गए और उनकी मौत हो गई। मंगलवार सुबह लोगों ने देखा तो दोनों की मौत हो चुकी थी। अधिकारियों ने बताया कि मध्य और उत्तरी जिलों के कई इलाकों से पेड़ उखड़ने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। अधिकारियों ने कहा कि पानी छोड़ने के लिए मलंकार और कल्लारकुट्टी बांधों के शटर खोल दिए गए हैं। इस वजह से पेरियार, मुथिरापुझा, थोडुपुझा और मुत्तुपुझा नदियों के तटों पर रहने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है।

21 जुलाई को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, राहुल हो सकते हैं शामिल, टीएमसी की दूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। मोदी सरकार के लिए दोबारा सत्र में आने के बाद यह पहली बड़ी परीक्षा होगी। यही कारण है कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजजू संसद के बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक 21 जुलाई को सुबह 11 बजे मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, दिल्ली में होगी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अधीन, सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो सकता है।

विशेष रूप से, यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विपक्ष के नेता और कांग्रेस संसद राहुल गांधी की पहली अपेक्षित उपस्थिति है। बैठक का उद्देश्य आगामी सत्र के लिए प्रमुख एजेंडों और रणनीतियों पर चर्चा करना है। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने पुष्टि की कि बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। उन्होंने 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में उद्धृत किया, जो 1993 में कोलकाता पुलिस गोलीबारी की घटना के दौरान दुखद रूप से मारे गए 13 कांग्रेस समर्थकों की याद में हर साल मनाया जाता है। यह घटना पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार के तहत राज्य



सचिवालय, राइटर्स बिल्डिंग तक मार्च के दौरान हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट (2024-25) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगी। संसद सत्र एक दिन पहले शुरू होगा और 12 अगस्त को समाप्त होगा। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स लिखा था कि भारत के राष्ट्रपति ने, भारत सरकार की सिफारिश पर, 22 जुलाई, 2024 से 12 अगस्त, 2024 तक बजट सत्र, 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई, 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा।

फिर गरमाया कावेरी जल विवाद, नाराज सीएम स्टालिन ने की सर्वदलीय बैठक, कर्नाटक का है अपना दावा

नयी दिल्ली (एजेंसी)। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु को कावेरी जल की कम मात्रा जारी करने पर कर्नाटक सरकार का रुख अत्यधिक निंदनीय है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कावेरी जल विवाद पर आज सर्वदलीय बैठक की। एमके स्टालिन ने कहा कि इस सर्वदलीय बैठक में तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने से इनकार करने पर कर्नाटक सरकार की कड़ी निंदा की गई। हम सीडब्ल्यूआरसी से आग्रह करते हैं कि वह कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सीडब्ल्यूआरपी के आदेश के अनुसार तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने का आदेश दे।

15 जुलाई, 2024 तक, कर्नाटक के चार मुख्य बांधों में कुल भंडारण 75.586 टीएमसी फीट है, तमिलनाडु के मेट्टूर जलाशय में जल स्तर मात्र 13.808 टीएमसी फीट है। किसानों ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु के लिए कावेरी जल छोड़ने की मांग को लेकर त्रिची, थिड्डे नगर में कर्नाटक बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कावेरी के पानी के कारण 20 वर्षों से अधिक समय से मुकदमेबाजी चल रही है। यह एक राजनीतिक मुद्दा है जिस पर 150 वर्षों से अधिक समय से बहस चल रही है।

कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद पर बढ़ते तनाव के बीच, उपमुख्यमंत्री डीके



शिवकुमार ने आपसी समझ की आवश्यकता पर जोर देते हुए बातचीत और सहयोग के लिए खुलापान व्यक्त किया है। शिवकुमार ने जल आवंटन पर चल रही चर्चा को संबोधित करते हुए कहा, 'तमिलनाडु को मिलने का पूरा अधिकार है, जैसे हम मिलते हैं। हम उनकी बैठक पर आपत्ति नहीं करते हैं। यह उनका कर्तव्य है।' उन्होंने तमिलनाडु की हालिया कार्रवाइयों पर सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया लेकिन कावेरी क्षेत्र में जल प्रवाह में सकारात्मक विकास पर प्रकाश डाला। इस बीच, बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि

राज्य तभी पानी छोड़ सकता है, जब उसके पास होगा। उन्होंने कहा, 'सीडब्ल्यूआरसी (कावेरी जल विनियमन समिति) आमतौर पर अपना फैसला आगस्त में देती है, लेकिन इस साल जुलाई में दिया गया। पिछले साल सूखा पड़ा था और इस साल भी हमें 30 फीसदी बारिश की कमी के साथ ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हम पानी तभी छोड़ सकते हैं जब हमारे पास पानी होगा। यह बारिश पर निर्भर करता है। अगर बारिश अच्छी होती है तो हम तमिलनाडु की मांग से ज्यादा पानी छोड़ सकते हैं।'

बच्चों में मौत का नया नाम... चांदीपुरा वायरस, सीधा मस्तिष्क पर हमला, दो दिन में मौत

उदयपुर (एजेंसी)। गुजरात के बाद अब राजस्थान में चांदीपुरा वायरस के मामले मिले हैं। उदयपुर के आदिवासी इलाके के कुल 2 बच्चों में यह लक्षण मिले थे। जिसमें से एक बच्चे की गुजरात के हिममतनगर के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। वहीं एक और 4 वर्षीय बच्चा वायरस की चपेट में है। हालांकि उसकी हालत खतरों से बाहर है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक यह वायरस सीधा मस्तिष्क पर हमला करता है। सबसे पहले पन्तू के लक्षण दिखते हैं, फिर बच्चा कोमा में चला जाता है।



दो मामले सामने आने के बाद मेडिकल विभाग की टीम की ओर से उनके गांवों में जाकर अन्य बच्चों के सैंपल ले रहे हैं। साथ ही परिवार के लोगों के भी सैंपल लेकर पुणे स्थित लैब में भेजे जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में स्वास्थ्य विभाग के हवाले से बताया गया है कि चांदीपुरा वायरस साल 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में फैला था। वहीं से इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा है। यह वायरस बारिश के वक्त फैलता है।

मच्छर और मक्खियों से फैलता है। ये दो मामले सामने आने के बाद मेडिकल विभाग ने गुजरात से सटे सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता दिखा रही है। बता दें कि 27 जून को उदयपुर के आदिवासी अंचल के नयाखंड के पास बलीचा गांव के एक मासूम की मौत हुई थी। हालांकि तब इस मौत को गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं जब गुजरात में कुछ बच्चों की मौत हुई, तब उसमें चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए गए। इसके बाद जब उदयपुर में एक और बच्चे की मौत हुई तब सामने आया कि उसमें भी चांदीपुरा के लक्षण थे। चांदीपुरा वायरस से लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों ने आदिवासी अंचल में हड़कण मचा गया है।

भाजपा की हार का निकाला सार...सविधान बदलने, आरक्षण खत्म, अतिआत्मविश्वास और विदेशी ताकतों का हाथ

-सभी नेताओं ने माना बांड मोदी का जलवा कायम

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव के नतीजे भाजपा की उम्मीदों से पारे रहे। उसके बाद से ही पार्टी में मंथन का दौर जारी है। इस लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में अब तक मीटिंग्स हो चुकी हैं। इन बैठकों में कुछ दिलचस्प सवाल भी उठे हैं कि आखिर भाजपा को चुनाव में इस्तरह के नतीजे क्यों देखने पड़े। बैठकों में राज्य के नेताओं के अलावा केंद्रीय स्तर से भी नेताओं को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा जा रहा है। यूपी में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मौजूद थे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन समीक्षा बैठकों में 7 बातें प्रमुखता से कही जा रही हैं।

बैठक में एक बात सभी ने कही कि विपक्ष की ओर से संविधान बदलने और उसके आधार पर आरक्षण खत्म करने की अफवाह फैलाई गई। इसका असर यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दिखाई दिया, जहाँ ओबीसी और दलित वर्ग की अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी ऐसी ही चर्चा हुई। वहां सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इन अफवाहों के चलते नतीजे खराब हुए हैं। सीएम शिंदे ने माना कि एनडीए विपक्ष की ओर से फैलाई गई इन अफवाहों की काट नहीं कर सका। लेकिन भाजपा की मीटिंग्स में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विदेशी ताकतों का दखल था। राजस्थान में हुई समीक्षा बैठक में

सवाल उठा था। वहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विनय सहस्रबुद्धे की मौजूदगी में हुई मीटिंग में कहा गया कि इन चुनावों में विदेशी हाथ था। विदेशी ताकतें चाहती हैं कि भारत से मोदी के शासन को खत्म कर दिया जाए। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसा ही संकेत दिया। सभी समीक्षा बैठकों में एकसुर से कहा गया कि कांग्रेस के 99 तक पहुंचने की वजह गठबंधन है। यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गठबंधन का फायदा मिला है और सरकार के खिलाफ जाने वाला वोट जब एकजुट हुआ...भाजपा को नुकसान हुआ और कांग्रेस फायदा ले गई। क्या इन चुनाव नतीजों ने बांड मोदी पर सवाल खड़े किए हैं? भाजपा में सभी नेता एकजुटता के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का जलवा कायम रहने की बात कर रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि पार्टी ने आत्मविश्वास, आपसी कलह की वजह से नुकसान उठाना है, लेकिन पीएम मोदी का जलवा जनता के बीच पहले की तरह कायम है। महाराष्ट्र में देवेद्र फडणवीस ने डिटी सीएम के पद से इस्तीफा तक देने को कह दिया था और खराब नतीजों की जिम्मेदारी भी ली थी। अतिआत्मविश्वास के चलते हार की बात भाजपा में लगातार कही जा रही है। योगी ने कहा कि हम लोग अतिआत्मविश्वास में आ गए। इसका नतीजा है कि चुनाव नतीजों के बाद अब जो विपक्ष कहीं कौनों ने बैठ था,

पाकिस्तान कश्मीर में नहीं हुआ कामयाब...जम्मू में बढ़ा रहा आतंकी गतिविधि : पूर्व डीजीपी

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी कुलदीप हुड्डा ने जम्मू में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर प्रतिक्रिया दी है। पूर्व डीजीपी हुड्डा ने कहा, पाकिस्तान का मिशन साफ है। वह अब जम्मू में गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में कामयाब नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कश्मीर में पाकिस्तान का सफाया हुआ और इसलिए अब वैसी जगह ढूँढ रहे हैं, जहां पर सुरक्षाबलों की कमी है। आमतौर पर जिन क्षेत्रों में शांति रही है, अब उन जगहों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे सेना का ध्यान जम्मू में बढ़ रही आतंकी घटनाओं की ओर जाए, जिससे वे कश्मीर में फिर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके। पूर्व डीजीपी हुड्डा ने कहा कि बीते कुछ समय में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए घुसपैठ को रोकने के लिए प्रयास किया जाए, चाहे तकनीकी या ह्यूमन सॉल्यूमेंट की जरूरत है, ऐसी सभी चीजों की मदद ली जाए। पाकिस्तान को डील करने के तरीकों में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि वह पिछली घटनाओं से सबक लेने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, उरी हमले के बाद भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान खामोश बेट गया था। मगर अब आतंकियों ने अपना एजेंडा फिर शुरू किया है। इसलिए अब और भी जरूरी हो जाता है कि भारत उनके खिलाफ एक्शन ले। जम्मू-कश्मीर में आतंकीवाद को बढ़ावा देने की जो कोशिश की जारी है, उन्हें नाकाम किया जाए।

अब फिलिस्तीन की मदद को आगे आया भारत, 2.5 मिलियन डॉलर की भेजी पहली किस्त

नई दिल्ली (एजेंसी)। गाजा में महीनों से हमला और इजराइल के बीच युद्ध जारी है जिसमें हजारों बेगुनाह फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है और लाखों बेघर हो गए हैं जो शिविरों में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इजराइली हमलों के चलते उन तक मदद पहुंचा भी मुश्किल हो रही है। इसी बीच अब फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने 2024-25 के लिए पांच मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त भेज दी है। भारत ने सोमवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी जिसने 1950 से फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए प्रत्यक्ष राहत के कार्यक्रम चलाए हैं। गाजा में इजरायल-हमला युद्ध के बीच अपने कामकाज को बनाए रखने के प्रयास कर रहा है। पिछले कुछ सालों में फिलिस्तीनी शरणार्थियों और उनके कल्याण का समर्थन करने के अपने प्रयास में भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए 2023-24 तक 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता फिलिस्तीनी शरणार्थियों को प्रदान की है। हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित यूएन-आरडब्ल्यूए सम्मेलन में भारत ने कहा था कि वित्तीय मदद के अलावा वह एजेंसी के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर यूएन-आरडब्ल्यूए को दवाएं भी देगा और फिलिस्तीन के लोगों को एक सुरक्षित वक्त पर निर्भर मानवीय मदद को आपूर्ति के लिए अपने वादे को निभाएगा।

पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थनगर, हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते एक माह से अपने सपनों के घर को तोड़े जाने की भ्रमक खबरों से परेशान पंतनगर, इंद्रप्रस्थनगर एवं रहींमनगर आदि क्षेत्रों के लोगों की समस्या का समाधान कर दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे प्रभावित परिवारों के भय और धम का समाधान करते हुए ने मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थनगर, वहां निवासित लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। संबंधित प्रकरण पर एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिह्नंकन किया गया है। फ्लड प्लेन जोन में निजी भूमि भी सम्मिलित है। लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की न तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और न ही कोई प्रस्ताव है। निजी भूमियों में बने निजी भवनों के स्वस्तीकरण का कोई विषय विचारार्थीन नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फ्लड प्लेन जोन चिह्नंकन के दौरान भवन निर्माणों पर लगाये गये संकेतों से आम जन में भय और धम फैला है, इसका कोई औचित्य नहीं था और इसके लिए जवाबदेही तय



की जाए। मुख्यमंत्री ने उक्त क्षेत्र में साफ-सफाई व जनसुविधाओं के विकास के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल क्षेत्र में विजिट करें, लोगों से मिलें और उनका भय और धम दूर किया जाए। प्रभावित परिवारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना बेवक विक्सित करने में यदि कोई निजी भूमि पर बना भवन

'आप' को दपतर के लिए जगह दीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को दिया आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपने पार्टी कार्यालय के लिए सामान्य पूल से अस्थायी आधार पर एक आवास इकाई आवंटित करने के आम आदमी पार्टी (आप) के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को 25 जुलाई तक का समय दिया। 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आप को राज उभेन्सू में अपना कार्यालय 15 जून तक खाली करने के लिए कहा क्योंकि विवादाधीन भूमि न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी। 15 जून को उच्च न्यायालय ने केंद्र को छह सप्ताह के भीतर अस्थायी आवास के लिए पार्टी के अनुरोध पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।



वह अब उखल रहा है। वहीं भाजपा में आपसी कलह की बातें खूब कही जा रही हैं। पिछले दिनों संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी आए थे। तब कई नेताओं ने कहा कि आपसी कलह के चलते तमाम सीटें गंवा दीं। मुजफ्फरपुर जैसी हाईप्रोफाइल सीट की खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि यहां संगीत सोम और संजीव बाबिल्यान के बीच आपसी कलह के चलते नतीजा खिलाफ आया है।